कमल संदेश
ikf{kd if=dk

**संपादक**

**प्रभात झा, सांसद**

**कार्यकारी संपादक**

**डॉ. शिवशक्ति बक्सी**

**संपादक मंडल**

**सत्यपाल**
**संजीव कुमार सिन्हा**

**कला संपादक**

**धर्मेन्द्र कौशल**
**विकास सैनी**

**सदस्यता शुल्क**

**वार्षिक : 100/-**
**त्रि वार्षिक : 250/-**

**संपर्क**

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDI : +91(11) 23387887
**पता** : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

**ई–मेल**

kamalsandesh@yahoo.co.in

**प्रकाशक एवं मुद्रक** : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

# विषय–सूची

**अमर शहीद डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की 111वीं जयंती के अवसर पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी।**

**डॉ. मुकर्जी जयंती**

कार्यक्रम का आयोजन..... 6
भारतीय जनसंघ ही क्यों ?..... 7

**लेख**

पूर्ववर्ती राष्ट्रपति चुनावों के कुछ संस्मरण
**–लालकृष्ण आडवाणी**..... 9
मानवीय खाद्यान्न नीति की दरकार
**–विश्वनाथ सचदेव**..... 11
देवभूमि हिमाचल– एक अनूठी पहल
**–शोभा उपाध्याय**..... 13
आंकड़ों से नहीं आंखों से देखो गरीबी को
**–संजीव कुमार सिन्हा**..... 15
भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार
**–राम प्रसाद त्रिपाठी**..... 17

**अन्य**

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बही कमल की बयार..... 19
डॉ. साहिब सिंह वर्मा की 5वीं पुण्यतिथि..... 20
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ : संगोष्ठी का आयोजन..... 21
पुस्तक समीक्षा..... 29

**प्रादेशिक समाचार**

बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश..... 24
हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश..... 25
असम..... 26
छत्तीसगढ़..... 27

**बोध कथा**

# छोटी सी भूल

अनेक बार हम कुछ घटनाओं को छोटी से भूल कहकर छोड़ देते हैं; पर आगे चलकर उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है। इसे समझाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक प.पू. श्री गुरुजी यह बहुचर्चित कथा सुनाते थे। एक विधवा स्त्री और उसका इकलौता पुत्र गाँव में रहते थे। वह महिला बहुत कठिनाई से मेहनत-मजदूरी कर अपना और अपने पुत्र का पालन कर रही थी। माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने उसे गाँव के ही एक विद्यालय में भर्ती भी करा दिया।

एक बार वह बालक अपने साथी की पेंसिल चुरा लाया। घर आकर उसने वह माँ को दे दी। माँ ने चुपचाप उसे रख लिया। धीरे-धीरे वह और भी सामान लाने लगा। माँ ने सोचा कि यह छोटा है, डाँटने से नाराज न हो जाये, इसलिए वह चुप ही रहती। अब वह इधर-उधर से पैसे भी लाने लगा। इसी प्रकार होते-होते वह एक बड़ा अपराधी बन गया। एक बार डकैती और हत्या के अभियोग में वह पकड़ा गया और उसे फाँसी की सजा घोषित हो गयी।

फाँसी से पूर्व जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गयी, तो उसने अपनी माँ से मिलना चाहा। जब माँ सामने आयी, तो उसने कान में कुछ बात कहने के बहाने माँ का कान काट लिया। माँ दर्द से चीख पड़ी। वहाँ खड़े लोग उसकी आलोचना करने लगे। कारण पूछने पर उसने कहा कि मेरी इस दुर्दशा की दोषी मेरी माँ ही है। जिस दिन मैंने पहली बार चोरी की थी, यदि उसी दिन माँ ने कान खींचकर मुझे रोक दिया होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। इसीलिए मैंने माँ का कान काटा है।

स्पष्ट है कि भूल चाहे छोटी ही हो; पर तुरंत टोक देने से वह बड़ी होने से बच जाती है। ■

*व्यंग्य चित्र*

**हमें लिखें...**

**सम्पादक के नाम पत्र**

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

**आपकी राय एवं विचार**

**सम्पादक,**
**कमल संदेश**
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
**ई-मेल:**
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

# ''ये वार्ताकार नहीं पाक के चाटुकार हैं''

सम्पादकीय

Hkkरत आजादी के बाद से ही पाक का दंश झेल रहा है। भारत की सबसे बड़ी भूल थी कि वह अपनी शर्तों पर 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने भारत को अपनी शर्तों पर आजादी दी। हमने पहली गलती यह कर दी कि हमने अखंड भारत को खंडित कर आजादी ली। एक ओर जहां पाकिस्तान ने बंटवारे को मजहबी आधार दिया वहीं भारत ने अपना उदार चित्त दर्शाया कि जो आजाद भारत में रहेगा वह भारतीय होगा। हमारी इस उदारता को अंग्रेजों और पाकिस्तानियों ने कमजोरी मान ली। भारत ने हर बार पाक के विरुद्ध हुई लड़ाई में अपनी सांस्कृतिक उदारता का परिचय दिया, पर पाक ने सदैव धोखा दिया। ''पाक'' के साथ हमारा हर समझौता हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ। 'पाकिस्तान' का मसला वोटों की राजनीति को ध्यान में रखकर कभी हल नहीं किया जा सकता। यह मसला तो अपनी आंखों के सामने ''भारत माता'' को रखकर करना होगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए नियुक्त वार्ताकारों की जो 176 पृष्ठों की रिपोर्ट आयी है वह किसी भारतीय द्वारा नहीं बल्कि पाक के चाटुकारों की भूमिका में दिया गया प्रतिवेदन है। क्या वार्ताकारों को यह अधिकार है कि-

1. भारत को फिर से एक बार विभाजन के कगार पर खड़ा करे?
2. क्या डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का हश्र यह होगा?
3. क्या वार्ताकारों को पाक के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया था?
4. क्या भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का उन्हें अधिकार सौंपा गया?
5. क्या अलगाववाद को संवैधानिक मान्यता इस रिपोर्ट से नहीं मिलेगी?
6. क्या इस रिपोर्ट से सुरक्षाबलों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगेगा?
7. इस रिपोर्ट के प्रतिवेदन में कश्मीर तोड़ने की साजिश नहीं दिख रही?
8. जम्मू और लद्दाख के साथ घोर पक्षपात करने का अधिकार किसने दिया?
9. कश्मीर के पंडितों के मसले पर वार्ताकार चुप क्यों?

ऐसे एक नहीं अनेक सवाल हैं जो वार्ताकारों के इस प्रतिवेदन से उठ रहे हैं। कांग्रेस शायद समझ नहीं रही कि यह प्रतिवेदन नहीं कांग्रेस की मौत का वारंट है। कांग्रेस के लिए यह प्रतिवेदन नहीं बल्कि भाजपा के लिए वह हथियार है, जिससे भाजपा सोते भारतवासियों को जगा सकती है और देशभक्ति का ज्वार जागृत कर सकती है। ■

# डॉ. मुखर्जी का नेतृत्व और कर्तृत्व प्रेरणास्पद : गडकरी

भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 111वीं जयंती पर 6 जुलाई, 2012 को भाजपा केन्द्रीय कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय गोयल और श्री थावरचंद गहलोत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के प्रति अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए डॉ. मुखर्जी ने बलिदान दिया। श्री गडकरी ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने उस दौर में कश्मीर को लेकर 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे' का नारा देकर राष्ट्रवाद को पोषित करने का साहस दिखाया था। वे राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक थे। डॉ. मुखर्जी के विचार, नेतृत्व और कर्तृत्व आज वर्तमान स्थिति में हम सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। उनके द्वारा प्रेरित राष्ट्रवाद कि विचारधारा देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रवाद भाजपा की आत्मा है। आज देश बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के समक्ष बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत से प्रश्न खड़े हुए हैं। डॉ. मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम सभी इन चुनौतियों का सामना करेंगे और जात, पंथ, भाषा और लिंग का भेद न रखते हुए हमारी गौरवमयी संस्कृति और इतिहास से प्रेरणा लेते हुए विकास को आधार बनाकर आगे बढ़ें। आज देश में जो आर्थिक-सामाजिक-लैंगिक असमानता विद्यमान हैं उसे दूर करते हुए देश को सबल बनाने का संकल्प करें, यही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।■

# 'कश्मीर पर वार्ताकारों की रिपोर्ट लागू हुई तो देशव्यापी आंदोलन'

भाजपा संसदीय दल के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने संप्रग सरकार को चेतावनी दी कि यदि जम्मू-कश्मीर पर वार्ताकारों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अमल हुआ तो भाजपा 1953 की तर्ज पर देशव्यापी

आंदोलन शुरू करेगी। भारत की एकता के अमर बलिदानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 111वें जन्मदिन पर 9 जून को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री आडवाणी ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में दो विधान, दो निशान व दो प्रधान संबंधी संविधान विरोधी नियमों से छुटकारा दिलाने के लिए कुर्बानी दी थी। यदि मुखर्जी का बलिदान नहीं होता तो भारत के संविधान को जम्मू-कश्मीर में मान्यता नहीं मिलती। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि भारत के वार्ताकारों ने जो रिपोर्ट पेश की है उससे 1953 जैसे हालातों को न्यौता मिल रहा है। इस मौके पर डॉ. मुखर्जी की नातिन मंजू जी का भी अभिनंदन किया गया।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान के निदेशक सांसद श्री तरुण विजय की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम में श्री आडवाणी के अतिरिक्त पूर्व राज्यपाल सर्वश्री केदारनाथ साहनी, पार्थ सारथी, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री रविशंकर प्रसाद, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन, भाजपा मुख्यालय प्रभारी ओ.पी. कोहली, हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह-प्रभारी श्याम जाजू, पूर्व उपसेनापति जनरल मलिक, अरुण सिंह, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, पूर्व वित्त मंत्री प्रो. जगदीश मुखी सहित अनेक नेता उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री आडवाणी ने मुखर्जी की नातिन का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारत माता के सच्चे सपूत की पौत्री मंजू जी से श्री मुखर्जी के पारिवारिक संस्मरण सुनकर मन को तृप्ति हुई। मुखर्जी परिवार के विमान मुखर्जी तथा उनकी पत्नी के प्रति भी साधुवाद जताते हुए श्री आडवाणी ने मंजू को एक चित्र भी भेंट किया। यह ऐतिहासिक चित्र डॉ. मुखर्जी की अंतिम सभा का है, जिसके बाद उन्होंने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया था। उनकी रहस्यमय मृत्यु से सारा देश स्तब्ध रहा। उन्होंने श्रीनगर में इस बार डॉ. मुखर्जी की स्मृति में कार्यक्रम के आयोजन पर भी साधूवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री पार्थसारथी ने जम्मू-कश्मीर की दयनीय हालत पर चिंता जताई। श्री तरुण विजय ने कहा कि वार्ताकारों की रपट से संदेह होता है कि वह हुर्रियत के दफ्तर में बैठकर बनाई गई है। ■

# भारतीय जनसंघ ही क्यों?

✍ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

***भारतीय जनसंघ का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कानपुर में 29 दिसम्बर 1952 को संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ''भारतीय जनसंघ ही क्यों?'' इस विषय पर सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन दिया था। इसमें उन्होंने पार्टी की विचारधारा के बारे में विस्तार से उल्लेख किया था, जो आज भी हमारे लिए पाथेय है। हम इस अध्यक्षीय उद्बोधन के प्रमुख अंश यहां प्रकाशित कर रहे हैं:-***

## राष्ट्रीय दृष्टिकोण

जनसंघ की विचारधारा तथा कार्यक्रम की रूपरेखा का निर्माण इसके जन्म के पश्चात शीघ्र ही हो गया था। इनमें हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय, सभी मूलभूत समस्याओं पर विचार किया गया था। हमारे विचारधारा तथा कार्यक्रम पर होने वाली आलोचना तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं पर विचार करते हुए समय-समय पर हमने इनमें परिवर्तन भी किया है। जाति, मत अथवा संप्रदाय, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना हमारा यह दल सभी के लिए खुला है। स्वतंत्र भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता को जाति, संप्रदाय अथवा मतादि के आधार पर खड़ा करना एक घातक भूल होगी। बिना किसी भी भेदभाव के भारतीय नागरिक के अधिकारों की समानता भारत के संविधान का आधार है जो कि प्रत्येक जनतंत्रवादी देश के लिए आवश्यक है। पाकिस्तान द्वारा अपने संविधान को, जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी सन्निहित हैं, इस्लामी कानून तथा साम्प्रदायिक भेदभाव के आधार पर बनाने का प्रस्ताव उसकी प्रतिगामी प्रवृत्तियों को नग्न रूप में प्रस्तुत करता है।

अनेक शताब्दियों से भारत विभिन्न मतमतान्तरों को मानने वाले लोगों की मातृभूमि रहा है। उनके व्यक्तिगत आचारधर्म की, विशेषकर उपासना और आधारभूत सामाजिक कर्तव्यों संबंधी, सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता निर्विवाद है। नागरिक अधिकार तथा कर्तव्यों में सब समान हैं। स्वस्थ्य और प्रगतिशील सहयोग का भाव उत्पन्न करते हुए हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें। यह पारस्परिक सहिष्णुता, सद्भाव और अवसर की सच्ची समानता से ही संभव होगा। हमारे दल का द्वार बिना किसी प्रकार के जाति अथवा मत संबंधी भेदभाव के उन सभी के लिए खुला है जो हमारे कार्यक्रम तथा विचारधारा में विश्वास रखते हैं। यदि कुछ वर्ग हमारे साथ आना नहीं चाहते तो भी हम सर्वसाधारण जनता की सद्भावना तथा सहयोग लेकर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल यह भी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए उसने बनावटी हिन्दू-मुस्लिम एकता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। फलस्वरूप मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को राष्ट्र के हित में घातक समझौते पर समझौते स्वीकार करने पड़े। अन्त में जिन विघटनकारी वृत्तियों को कांग्रेस ने तुष्टिकरण के द्वारा जीतना चाहा था, उन्होंने कल्पनातीत भयंकर रूप धारण किया और उसका परिणाम देश का विभाजन हुआ। उपासना पद्धति को राष्ट्रीयता का आधार बनाने, या मतपरिवर्तित व्यक्तियों अथवा उनके वंशजों द्वारा मजहब के आधार पर देश का सफलतापूर्वक विभाजन कराने की घटना और कहीं नहीं सुनी। जनसंघ का मत है कि विभाजन से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, न भारत में, न पाकिस्तान में। इससे देश प्रत्येक प्रकार से दुर्बल हुआ है। यही नहीं जिस समस्या को हल करने के लिए विभाजन स्वीकार किया गया था वहीं और अधिक भयंकर हो गई है और एक शान्तिपूर्ण हल निकल नहीं पा रहा है। अत: हमारे सामने अखंड भारत कोई अवास्तविक स्वप्न अथवा नारा मात्र नहीं है। यह हमारी श्रद्धा का विषय है और वह लक्ष्य है जो जनता के सहयोग और समझ से प्राप्त होगा ही।

***स्वतंत्र भारत में किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता को जाति, संप्रदाय अथवा मतादि के आधार पर खड़ा करना एक घातक भूल होगी। बिना किसी भी भेदभाव के भारतीय नागरिक के अधिकारों की समानता भारत के संविधान का आधार है जो कि प्रत्येक जनतंत्रवादी देश के लिए आवश्यक है।***

## सुव्यवस्थित अर्थ-व्यवस्था

हमारा यह विश्वास है कि भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता की सर्वोच्च परम्परा के अनुरूप जनता के चारित्रिक तथा मानसिक विकास एवं भारत की पूर्ण आर्थिक उन्नति, इन दोनों के समन्वय पर ही देश की भावी

उन्नति आधारित है। आर्थिक स्वातन्त्र्य के बिना जो राजनीतिक स्वातन्त्र्य हमने प्राप्त किया है वह निरर्थक होगा। यह एक अत्यन्त दुखदायी स्थिति है कि भारत जैसा विशाल देश अपने प्राय: असीम प्राकृतिक साधनों तथा कच्चे माल के होते हुए दारिद्रय, रोग, अविद्या तथा पतन के गर्त में पड़ा रहे। हमारे दल का यह विश्वास है कि देश को हिंसात्मक अशान्ति तथा विग्रह में बिना झोंके हुए भी हमारे लिए यह सम्भव है कि जनता के आर्थिक शोषण और मूक वेदनाओं का अन्त कर हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकें। अत: भूमि और कृषि, छोटे-बड़े और बीच के उद्योगों का संगठित विकास, तथा उत्पादन वृद्धि और उचित वितरण, आदि विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में जनसंघ का दृष्टिकोण यथार्थवादी और प्रगतिशील है। अवसर की सच्ची समानता तब तक सम्भव नहीं जब तक कि जनता के निर्धन तथा पिछड़े हुए वर्गों को उचित शैक्षणिक एवं आर्थिक सुविधायें प्राप्त न हो ताकि उनकी वे भारी कमियां दूर हो सकें जिनसे वे आज त्रस्त है।

## आध्यात्मिक पुनर्जागरण

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल आर्थिक विकास न तो मनुष्य के अन्त:करण को पूर्ण शान्ति दे सकता है और न उसके दृष्टि की पूर्ण प्राप्ति में सहायक होता है भारत ने उन मन:प्रवृत्तियों को जन्म दिया है जो उन्नति और प्रगति का दावा करने वाले अनेक देशों से भिन्न उसकी अपनी विशेषता है। जीवन में सादगी, सेवा और त्याग का भाव, संतोष तथा नि:स्वार्थ नि:स्पृहता का दृष्टिकोण, बन्धुत्व एवं पावित्र्य का भाव, शक्ति और विनम्रता, सहिष्णुता तथा ऐक्य का योग अनादि काले से सुस्कृत मानवीय आचार का आदर्श रहा है। हमारा देश अच्छाई तथा बुराई का एक विचित्र सम्मिश्रण है। मानव जीवन के गूढ़तम रहस्यों का उद्घाटन करने वाले सत्य को यहां अति सरल ढंग से उदार हृदय होकर प्रकट किया गया है। इन सत्यों को आचरण में प्रकट करने वाले इक्के-दुक्के उदाहरण अवश्य मिलते हैं किन्तु इन महान् शिक्षाओं के साथ अधिकांश लोगों के आचरण की संगति कठिनाई अवश्य पहुंचाएगा। प्रश्न केवल यह है कि यदि हम इसी गति से चलते रहे और दशा को अधिकाधिक बिगड़ने दिया तो क्या पीड़ित जनता का धैर्य अटूट बना रहेगा और क्या वे सदा ही इसी प्रकार चुपचाप सहन करते रहेंगे ? यदि सरकार द्वारा अपने कर्तव्यपालन में असफल होने पर जनक्षोभ उसके विरोध में एक बार भी भड़क उठा तो हमें बहुत अधिक धन-जन की हानि उठानी पड़ेगी, जो शायद अन्यथा बचाई जा सकती है।

इस योजना के इसी रूप में भी पूर्ण होने के सम्बन्ध में कुछ चेतावनी के शब्द कह देना आवश्यक है। इसको क्रियान्वित करने के लिए बनाई गयी व्यवस्था पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह आवश्यक है कि इस उद्देश्य के लिए ऐसे ही लोगों का चुनाव हो जो पूर्ण योग्य हो और जिनमें हृदय की विशालता तथा सेवा का भाव हो। इन गुणों के कारण वे केवल वेतन प्राप्त कर्मचारी न होकर, योजनाबद्ध राष्ट्रीय विकास के नवीन युग को लाने वाले निमित्त होंगे। अत: उनका चुनाव पक्षपात, संरक्षकता अथवा दलगत भावनाओं के अनुसार कदापि नहीं होना चाहिए। किसी भी संगठित योजना की सफलता के लिए सार्वजनीन सहयोग का सच्चा वातावरण आवश्यक है। इतने गाने-बाजे से स्थापित किए गये भारत सेवक समाज की प्रगति भी एक दल-निरपेक्ष संगठन के रूप में नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त आज के सत्ताधारियों द्वारा योजना का दुरुपयोग अपने दलीय स्वार्थों के लिए किए जाने की भी बहुत गुंजाइश तथा संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो इससे न केवल नितान्त आवश्यक सार्वजनीन सहयोग तथा उत्साह पूर्णत: समाप्त हो जाएगा वरन् इस योजना को चलाने की सारी व्यवस्था ही दूषित हो जाएगी और इस प्रकार इसकी सफलता के सभी अवसर नष्ट हो जायेंगे। योजना के अनुसार राज्य के द्वारा उठाये गये किसी भी निर्णय कार्य के उपर आदि से अन्त तक कठोर देखरेख रखना आवश्यक होगा। राज्य के द्वारा उठाये गये कुछ कार्यों में अच्छी सफलता मिली है, उदाहरणार्थ सिन्दरी का खाद का कारखाना, चितरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी, दामोदर घाटी कारपोरेशन आदि। इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि सामान की बरबादी और अन्य अनियमितता तथा भूलें जो पहले हो चुकी हैं, फिर भविष्य में भी दोहराई जाये।

प्रत्येक कार्य के अधीक्षण की पूर्ण व्यवस्था चाहिए और समय-समय पर उसकी प्रगति का पूरा विवरण जनता को प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार के सभी सार्वजनिक कार्यों का वातवरण नीचे से उपर तक सुव्यवस्था तथा सहकारिता से परिपूर्ण हो जिसका परिणाम ऊपर से नीचे तक सभी पर हो ताकि वे जनहितैषी राज्य की उच्चतम धारणाओं का योग्य रूप से प्रतिनिधित्व कर सकें। इस समय उत्पादन तथा वितरण की अनेकों इकाइयां निजी व्यवस्था के द्वारा भी चलाई जा रही है। अनेकों असुविधा के कारण वे अपनी पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही हैं। यदि उन्हें राज्य की ओर से उचित सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त हो तो वह भी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि में तथा बेरोजगारी के बढ़ते हुए संकट को रोकने में सहायक हो सकती है। ■

***हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि केवल आर्थिक विकास न तो मनुष्य के अन्त:करण को पूर्ण शान्ति दे सकता है और न उसके दृष्टि की पूर्ण प्राप्ति में सहायक होता है। भारत ने उन मन:प्रवृत्तियों को जन्म दिया है जो उन्नति और प्रगति का दावा करने वाले अनेक देशों से भिन्न उसकी अपनी विशेषता है।***

# पूर्ववर्ती राष्ट्रपति चुनावों के कुछ संस्मरण

लालकृष्ण आडवाणी

चौदहवें राष्ट्रपति चुनाव में दो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वियों, सरकारी पक्ष के प्रणव मुखर्जी और विपक्ष के प्रत्याशी पूर्णो संगमा ने गत् सप्ताह अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं।

पूर्ववर्ती चुनावों का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए मैंने इंगित किया था कि पूर्व के तेरह चुनावों में 1977 ही एकमात्र ऐसा अवसर था जब राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया।

मैं 1977 की कुछ यादें ताजा कर रहा हूं जो 19 महीने के आपातकाल के बाद की है। इस आपातकाल के दौरान राष्ट्र को नागरिक स्वतंत्रताओं का निर्दयी दमन देखना पड़ा जैसाकि ब्रिटिश शासन में भी नहीं देखने को मिला था।

स्वतंत्रता के बाद से यह पहला अवसर था जब कांग्रेस पार्टी नई दिल्ली की सत्ता गवां चुकी थी। 1977 के लोकसभाई चुनावों में कांग्रेस की पराजय पूर्णतया अप्रत्याशित थी। आपातकाल में हुई ज्यादतियों से मतदाता इतने गुस्से में थे कि उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से में कांग्रेस का सफाया हो गया था।

पंजाब (13), हरियाणा (9), हिमाचल (4), दिल्ली (7), चंडीगढ़ (1), उत्तर प्रदेश (85) और बिहार (54) की कुल 173 लोकसभाई सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली! मध्यप्रदेश (38) और राजस्थान (25) की कुल 63 सीटों में से कांग्रेस को मात्र 2 सीटें (दोनों प्रदेशों में से एक-एक) प्राप्त हो सकीं।

वह पहला अवसर था जब हम जनसंघ के सदस्य केंद्रीय सरकार में मंत्री बने। सरकार का नेतृत्व श्री मोरारजी देसाई कर रहे थे।

26 जून, 1975 को जिस दिन आपातकाल थोपा गया उस दिन मैं और अटलजी दल बदल विरोधी कानून के बारे में संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु बंगलौर गए हुए थे।

जब 25/26 जून की रात्रि को हजारों की गिरफ्तारियां हो रही थीं (इनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री मोरारजी देसाई और श्री चन्द्रशेखर शामिल थे), तब अटलजी, मधु दण्डवतेजी, श्याम नन्दन मिश्राजी और मैं, जो बंगलौर में संसदीय समिति की बैठक हेतु आए थे, को 26 जून की सुबह बंगलौर में ही गिरफ्तार कर लिया गया।

आपातकाल के ढाई महीने हमें रोहतक जेल भेजा गया, सिवाय इसके हमारा अधिकांश बंदीकाल बंगलौर सेंट्रल जेल में रहा।

बंगलौर में बंदी के रुप में हमारे वकील के रुप में श्री रामा जायॅस और श्री संतोष हेगड़े थे (दोनों ही बाद में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश बने)। बाद में, जब हमारी औपचारिक नजरबंदी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय में विचारार्थ हेतु आई तब हमारी ओर से श्री एम.सी. छागला, श्री शांति भूषण और श्री वेणु गोपाल जैसी प्रमुख विधिक हस्तियों ने केस लड़ा।

'आर्गनाइजर' में पत्रकार के रुप में काम करते हुए ही मोरारजीभाई, चन्द्रशेखरजी और डा. लोहिया जैसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मेरा संबंध 1970 में संसद में आने से पहले ही बन चुका था। अतः, जब श्री देसाई ने मुझे अपने मंत्रिमण्डल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया, तो अक्सर वह मुझसे मेरे मंत्रालयों से इतर विषयों पर भी अनौपचारिक रुप से विचार-विमर्श कर लेते

*मैं इस ब्लॉग में 1977 की कुछ यादें ताजा कर रहा हूं जो 19 महीने के आपातकाल के बाद की है। इस आपातकाल के दौरान राष्ट्र को नागरिक स्वतंत्रताओं का निर्दयी दमन देखना पड़ा जैसाकि ब्रिटिश शासन में भी नहीं देखने को मिला था।*

www.lkadvani.blog.in

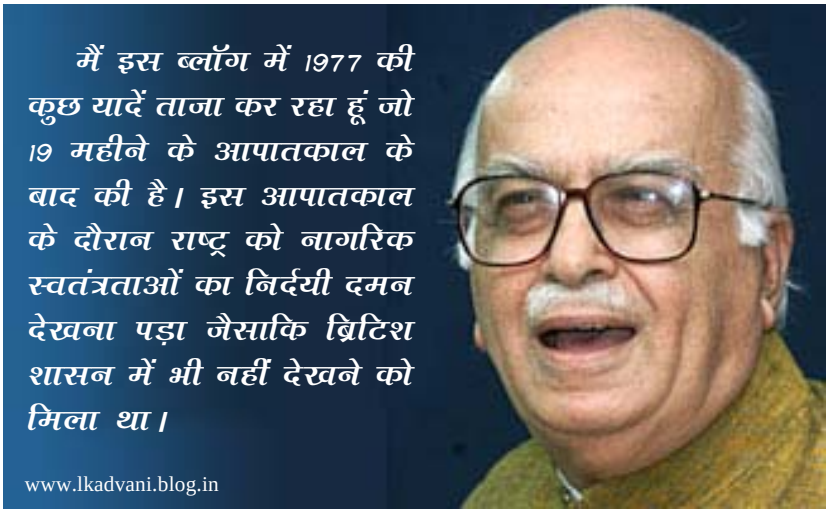

थे।

मुझे स्मरण आता है कि उनकी सरकार के शुरुआती दिनों में ही एक बार उन्होंने मुझसे पूछा, "तुम्हें क्या लगता है कि देश का नया राष्ट्रपति कौन होना चाहिए?"

जब मोरारजीभाई ने देश के राष्ट्रपति के बारे में मेरा मत पूछा तो बंगलौर से मेरा इतना लगाव हो गया था कि प्रधानमंत्री को मेरा स्वाभाविक जवाब था: क्यों नहीं न्यायाधीश श्री के.एस. हेगड़े, जिनकी वरिष्ठता को पीछे कर श्रीमती गांधी ने एक कनिष्ठ न्यायाधीश श्री ए.एन. रे को पदोन्नत कर दिया था। जब श्री रे मुख्य न्यायाधीश थे तभी सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा मीसाबंदियों के पक्ष में दिए गए फैसलों को रद्द कर दिया था। न्यायाधीश श्री एच.आर. खन्ना सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने इस फैसले के विरुद्ध अपनी असहमति दर्ज कराई थी।

मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि मोरारजीभाई मेरे मत से सहमत थे। लेकिन उन्होंने कहा कि संजीव रेड्डी यह मानते हैं कि 1969 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड द्वारा उन्हें राष्ट्रपति पद का अधिकृत प्रत्याशी चुना गया था, परन्तु कांग्रेस की ही नेता और प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें इस पद से वंचित कर एक स्वतंत्र प्रत्याशी श्री वी.वी. गिरी को समर्थन देने में कोई गुरेज नहीं हुई। मोरारजीभाई के निर्णय की न्यायसंगतता को मैं समझ सकता हूं। अत: श्री रेड्डी तब राष्ट्रपति बने और न्यायाधीश हेगडे लोकसभा के स्पीकर।

पूर्ववर्ती अधिकांश राष्ट्रपति चुनाव संसद सत्र के चलते सम्पन्न हुए।

मुझे याद है कि 1974 में छठे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सभी विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई ताकि विचार और निर्णय हो सके कि कांग्रेस के प्रत्याशी फखरूद्दीन अली अहमद के विरोध में एक सर्वमान्य विपक्ष का प्रत्याशी कौन हो। मैं इस बैठक में जनसंघ की तरफ से शामिल था। संक्षिप्त विचार-विमर्श के पश्चात् रिव्यूलेशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आर.एस.पी.) के श्री त्रिदीब चौधरी के नाम पर सहमति हुई।

त्रिदीबजी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जहां जनसंघ के अधिकाधिक में विधायक थे, में साथ जाने का मुझे स्मरण हो आ रहा है। इन राज्यों में रेल यात्रा के दौरान त्रिदीबजी ने मुझे कहा कि उनके अन्य वामपंथी साथी साधारणतया आर.एस.एस. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और जनसंघ के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, लेकिन वह सदैव आर.एस.एस. को आदर से देखते हैं। एक स्कूली छात्र होने के नाते उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को अक्सर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की बैठकों में भाग लेते देखा, जो अंग्रेजों के विरूद्ध एक भूमिगत क्रांतिकारी संस्था थी।

इस प्रकार की बातचीत हमारे पार्टी सहयोगियों को शिक्षित करने में काफी उपयोगी सिद्ध हुई कि देशभक्ति-विभिन्न वैचारिक तत्वों को भी एक डोर में बांधने का शक्तिशाली बंधन हो सकती है।

सन् 1977 में आपातकाल के तुरंत बाद होने वाले सातवें राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस इतनी हतोत्साहित थी कि वह कोई प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाई, अत: संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए।

1974 में विपक्ष के एक सर्वमान्य प्रत्याशी के सम्बन्ध में जनसंघ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण 1982 में भी दोहराया गया।

विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों की प्राथमिक बैठक में यह सुझाया गया कि कांग्रेस पार्टी के ज्ञानी जैल सिंह के मुकाबले किसी वरिष्ठ सांसद के नाम पर विचार किया जाए।

जब किसी ने श्री हीरेन मुखर्जी का नाम लिया तो मैं सबसे पहला था जिसने इस पर तुरंत सहमति दी।

संसद की प्रेस दीर्घा में अक्सर जाने वाले पत्रकार के रूप में सदैव मेरा मानना रहा कि पहली लोक सभा (1952-57) में जो दो सर्वाधिक श्रेष्ठ वक्ता थे वे दो मुखर्जी ही थे - श्यामा प्रसाद और हीरेन। मैं जानता हूं कि दोनों एक-दूसरे का काफी सम्मान करते थे।

अत: इस बैठक में, श्री हीरेन मुखर्जी का नाम सर्वसम्मति से तय हुआ।

दो दिन बाद, सीपीआई के प्रतिनिधि ने बताया कि हीरेन दा का नाम किसी प्रकार मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, अत: एक नए नाम पर विचार करने के लिए विपक्ष की बैठक बुलानी पड़ेगी।

उक्त बैठक विधिवत सम्पन्न हुई। इस दूसरी बैठक में मैंने न्यायाधीश एच0आर0 खन्ना का नाम सुझाया। इस नाम पर तुरंत सभी की सहमति बनी।

**पश्च्यलेख (टेलीपीस)**

न्यायमूर्ति खन्ना का 95 वर्ष की आयु में 25 फरवरी, 2008 को निधन हो गया। उनके युगांतरकारी निर्णय के बाद 'दि न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अपने सम्पादकीय में लिखा था: "यदि भारत कभी पीछे मुड़कर अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को देखेगा, जिसने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहले अठारह वर्षों में जो गौरवशाली उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो निश्चित रूप से कोई न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का स्मारक सर्वोच्च न्यायालय में अवश्य बनवाएगा।"■

***सन् 1977 में आपातकाल के तुरंत बाद होने वाले सातवें राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस इतनी हतोत्साहित थी कि वह कोई प्रत्याशी तक खड़ा नहीं कर पाई, अतः संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए।***

# मानवीय खाद्यान्न नीति की दरकार

✍ विश्वनाथ सचदेव

;k ग गुरु बाबा रामदेव के पास एक रामबाण नुस्खा है देश की सारी समस्याओं के लिए विदेशों में पड़े भारत के काले धन को वापस लाओ। वे अरबों-खरबों के आंकड़े देकर बताते हैं कि उस पैसे से देश के हर आदमी के हिस्से में इतना आ सकता है कि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जायें। बड़ा सुहावना लगता है यह सुनना और हैरानी होती है कि इतनी आसान बात हमारे राजनेताओं खासकर सरकार में बैठे राजनेताओं, को समझ क्यों नहीं आती? खैर, वह काला धन तो दूर की कौड़ी है, पता नहीं कितना है, किसका है, कैसे वापस आ सकता है और कैसे बंटेगा, पर जो कुछ हमारे पास है, हम उसे भी बांट कर खाना कहां सीख पाये हैं। मजे की बात तो यह है कि कोई उसकी बात भी नहीं करता।

आंकड़े बता रहे हैं कि आज हमारे देश के पास खाद्यान्न का भण्डार, चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। लेकिन इसके बावजूद देश की आबादी का पांचवां हिस्सा अर्थात् हर पांच में से एक आदमी भूखा है। कुपोषण का शिकार है। खाद्यान्न इतना है कि हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए जगह नहीं है। खुले मैदानों में सड़ रहा है अनाज। और सड़ने वाले उस अनाज की मात्रा लाखों टन है। हमारी सरकारों की घोषित कृषि-नीति के दो प्रमुख उद्देश्य बताये गये हैं: किसानों को उनकी फसल के लिए खुले बाजार में मिलने वाली कीमत से अधिक देना और दूसरा देश के गरीबों को खुले बाजार की तुलना में कम कीमत पर खाद्यान्न मुहैया करवाना। नीति में कहीं खोट नहीं है। फिर भी हालत यह है कि अनाज उगाने वाला किसान भी भूखा है और गरीब भी। लेकिन क्यों?

देश में अनाज की कमी नहीं है। पिछले दो दशकों में हमारा खाद्यान्न का उत्पादन कम से कम पचास प्रतिशत बढ़ा है। सरकार किसानों से अनाज खरीद भी रही है। गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज देने की योजनाएं बनती रहती हैं, घोषणाएं होती रहती हैं। इन योजनाओं पर सरकार प्रतिवर्ष 750 बिलियन रुपये खर्च करती है। देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक प्रतिशत। फिर भी देश की 21 प्रतिशत आबादी कुपोषित है। यह सारे आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के हैं। सरकार के नये खाद्यान्न सुरक्षा कानून के फलस्वरूप यह राशि दुगनी से भी अधिक हो जायेगी। लेकिन क्या उससे जरूरतमंद तक अनाज पहुंचने की गारंटी भी मिल जायेगी? विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार भारत की राज्य सरकारों द्वारा गोदामों से उठाये गये अनाज में से लगभग 41 प्रतिशत ही भारत के घरों तक पहुंच पाता है। शेष भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है।

***आंकड़े बता रहे हैं कि आज हमारे देश के पास खाद्यान्न का भण्डार, चीन को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। लेकिन इसके बावजूद देश की आबादी का पांचवां हिस्सा अर्थात् हर पांच में से एक आदमी भूखा है। कुपोषण का शिकार है। खाद्यान्न इतना है कि हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए जगह नहीं है। खुले मैदानों में सड़ रहा है अनाज।***

आये दिन देश के किसी न किसी हिस्से से कुपोषण से मरने वालों की खबरें मिलती रहती हैं। किसानों की आत्महत्याएं रोजमर्रा की बात हो गयी है। सरकार की सारी घोषित नीतियों, संकल्पों के बावजूद न भूख कम हो रही है, न गरीबी। सरकार ने मान लिया है कि सत्ताइस रुपए रोज कमाने वाला भारतीय गरीब नहीं है, लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं है कि इन सत्ताइस रुपयों से अनाज की सस्ती दुकानों से भी पर्याप्त अनाज नहीं खरीदा जा सकता।

लाखों रुपये खर्च करके बने शाही शौचालय वाले योजना आयोग में बैठे अफसरों को यह तो पता है कि पिछले तीन सालों में देश में खाद्यान्न-उत्पादन के सारे पिछले रिकार्ड टूटे हैं, उन्हें यह भी पता है कि हमारे अनाज के भण्डार भी पहले इतने कभी नहीं भरे थे, लेकिन वे यह जानने-मानने से इनकार करते हैं कि भूखे पेट तक यह अनाज नहीं पहुंच पा रहा। भूखे पेट तक अनाज पहुंचाने के दो ही तरीके हैं : पहला, हर जरूरतमंद के जेब में इतना पैसा हो कि वह अपनी जरूरत का अनाज खरीद सके और दूसरा, सरकारी गोदामों से भूखे को अनाज बांट दिया जाये। पर हमारे नीति-निर्धारकों को इनमें से कोई भी बात रास नहीं आ रही। आम आदमी की आर्थिक स्थिति सुधारने को बनायी 'गरीबी की रेखा, ऊपर-नीचे करके ही वे अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। इसी जादुई रेखा का कमाल है कि सन् 2004-05 में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन-यापन करने वाले देश में 37.2 प्रतिशत थे और 2009-10 में यह संख्या 29.8 प्रतिशत रह गयी। घट गयी देश की गरीबी। भर गये कुछ ज्यादा लोगों के पेट! इस गरीबी और भूख को हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री "राष्ट्रीय शर्म" तो

मानते हैं, लेकिन भूखे तक अनाज पहुंचाने की किसी व्यवस्था का आगाज आज तक नहीं हो सका।

खाद्यान्न के मामले में उच्चतम न्यायालय के सलाहकार बिराज पटनायक ने कुछ अर्सा पहले भूखे तक अनाज पहुंचाने के संदर्भ में कहा था, "हमारी इस (भूख की) समस्या का कारण यह है कि हम किसानों से खरीदा अनाज भूखों में बांटने को तैयार नहीं हैं। (गोदामों, खुले मैदानों में) सड़ने वाले इस अनाज की सही जगह भूखों का पेट ही है।"

यह बात किसी ने पहली बार नहीं कही है। लेकिन जब-जब यह बात कही गयी, इसे अवैज्ञानिक और अर्थशास्त्र के नियमों के विरुद्ध बताया गया। कहा गया कि व्यवस्थाएं ऐसे नहीं चलतीं। तो कैसे चलती है व्यवस्था? सच बात तो यह है कि एक तरफ लोग भूखों मरें और दूसरी ओर अनाज सड़ता रहे, इसे व्यवस्था कहा ही नहीं जा सकता। यह कुव्यवस्था भी नहीं है। अराजकता है यह। अमानवीयता भी।

संसद के मानसून सत्र में नयी खाद्यान्न नीति की घोषणा की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी किसी भी नीति का आधार सिर्फ यही हो सकता है कि किसान को वाजिब दाम मिलें और भूखे को रोटी। देश के विकास का पैमाना विकास की ऊंची दरें नहीं हो सकता। संसद में करोड़ोंपतियों की बढ़ती संख्या भी देश की आर्थिक खुशहाली की परिचायक नहीं हैं। विकास की कसौटी सिर्फ यह हो सकती है कि हर पेट को रोटी मिलती है या नहीं। भरे भण्डार और भूखे पेट एक विडम्बना को ही रेखांकित नहीं करते, देश की सोच में अपरिपक्वता को भी दर्शाते हैं। आपराधिक अपरिपक्वता है यह।

देश का अनाज उचित भण्डारण के अभाव में सड़े नहीं, यह जरूरी है। लेकिन जरूरी यह भी है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनायी जाये कि यह अनाज जरूरतमंद तक पहुंच सके। अनाज पर सबसिडी की नीति भी अपर्याप्त लग रही है। न तो इस नीति का उचित निर्धारण हो रहा है और न ही इसका क्रियान्वयन हमारी स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप है। खाद्यान्न सुरक्षा विधेयक पर हुई बहस के दौरान बहुत सारी बातें सामने आयी हैं, पर हमारे नीति-निर्धारकों को इस बात को भी अपने सामने रखना होगा कि हमारे जैसे आर्थिक विषमता वाले समाज में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना ही भूख की समस्या का समाधान नहीं है।

भूख की राजनीति करने वालों को यह बात भी समझनी होगी कि असमानता और कुपोषण की समस्याओं के हल के लिए एक मानवीय खाद्यान्न नीति की आवश्यकता है। ऐसी नीति जिसमें अनाज उत्पादक और अनाज-उपभोक्ता दोनों के हित सुरक्षित हों। कुपोषण से मरने और भूख से संतप्त रहने की "राष्ट्रीय शर्म" को समाप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम गरीबी की काल्पनिक रेखाओं वाले अर्थशास्त्र से उबरें और ऐसी यथार्थवादी नीतियां अपनायें कि किसी का भूख से मरना और कहीं अनाज का सड़ना हमें अपराध लगे। ■

***(दैनिक ट्रिब्युन से साभार)***

# प्रधानमंत्री के वक्तव्यों में विरोधाभास : डॉ. जोशी

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 29 जून, 2012 को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह देश की अर्थव्यवस्था के संबंध में बयान देते आ रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, कभी वे कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था अगले कुछ माह में पटरी पर आ जाएगी। अब वित्तमंत्री का पद अपने जिम्मे लेने के बाद उनका बयान आया है कि पूर्व वित्तमंत्री श्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में लिए गए आर्थिक निर्णयों की पुन:समीक्षा की जाएगी।

प्रधानमंत्री के ताजा बयान से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच तालमेल का घोर अभाव था। नेतृत्वहीनता की वजह से या तो प्रधानमंत्री जी पूर्व वित्तमंत्री को आर्थिक निर्णयों के मामले में दिशानिर्देश देने में अक्षम थे अथवा प्रधानमंत्री के निर्देश देने के बावजूद श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा उसे नजरअंदाज कर दिया जाता रहा। क्या प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रधानमंत्री की अवहेलना किए जाने की वजह से ही उन्हें कैबिनेट से रास्ता दिखाते हुए और पदोन्नति देते हुए राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया?

भारतीय जनता पार्टी आरंभ से ही कहती आ रही है कि देश की अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त हो चुकी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख सेक्टर -कृषि, उद्योग, विनिर्माण, इत्यादि की स्थिति बेहद चिंताजनक है। उचित माहौल के अभाव में देश के उद्यमी बाहर निवेश कर रहे हैं और बाहर के निवेशकर्ता भारत में निवेश करने से कतरा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह रहा है कि नीतिगत पंगुता की वजह से रूपए का अवमूल्यन हो रहा है। देश के केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच भी तालमेल का घोर अभाव दिखाई पड़ रहा है। सरकार कह रही है कि देश की आर्थिक नीति के मामले में सभी मिल-जुलकर काम करें। भाजपा सरकार के साथ हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार है लेकिन सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनकी क्या कार्ययोजना है। ■

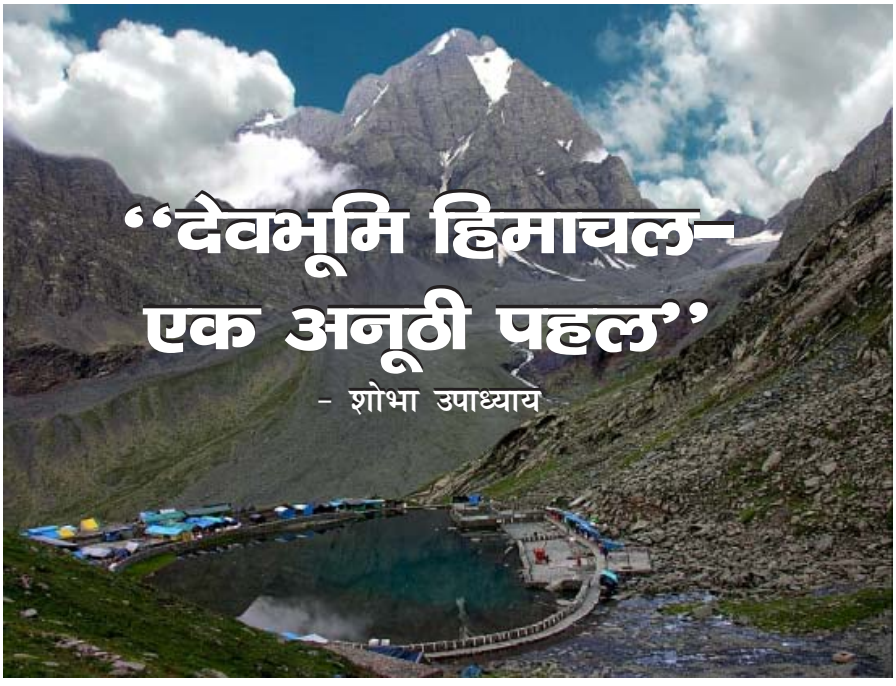

# ''देवभूमि हिमाचल– एक अनूठी पहल''

– शोभा उपाध्याय

***पिछले 50 महीनों के कार्यकाल में उच्चतम मापदण्डों पर खरा उतर कर प्रो. धूमल व उनकी टीम ने 64 कीर्तिमान स्थापित कर-अपनी उच्च क्षमता व जनता के प्रति निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया है।***

**''ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है?**
**ये कौन चित्रकार है,**
**ये कौन चित्रकार है?**

देवभूमि हिमाचल पर कदम रखते ही ये पंक्तियां जुबान पर आ जाती हैं- 'ईश्वर की अनोखी संरचना', 'प्रकृति का अनूठा उपहार'- कितना मोहक कितना सुखद।

प्रकृति की ये अलौकिक सुंदरता, अनुपम छटा-हरी भरी वादियों व शुद्ध वातावरण के साथ-साथ जब हर तरफ सुव्यवस्था व सुशासन हो तो-जीवन कितना सुलभ, कितना सुगम हो जाता है- ये देखने को मिलता है हमारे देश के इस गौरवशाली प्रदेश हिमाचल में। यहां के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेमकुमार धूमल ने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता के रूप में हिमाचल का कुशल नेतृत्व कर जिस राष्ट्रीय स्तर पर इसे निखारा है उससे देश व पार्टी दोनों ही गौरवान्वित हुये हैं। चहुंमुखी प्रतिभा के धनी, सरल व मृदुभाषी, व्यक्तित्व के साथ कर्त्तव्यनिष्ठ व दृढ़ इरादे-निश्चय ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व की पहचान है। पिछले 50 महीनों के कार्यकाल में उच्चतम मापदण्डों पर खरा उतर कर प्रो. धूमल व उनकी टीम ने 64 कीर्तिमान स्थापित कर-अपनी उच्च क्षमता व जनता के प्रति निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस महान उपलब्धि पर बधाई देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने एक सभा में कहा कि जिस तरह 'सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई है- उसी तरह हमारे धूमल जी 100 (पुरस्कार) सेंचुरी बनाकर ही चैन लेंगे, ऐसा विश्वास है। दिन प्रतिदिन रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवानों की संख्या बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज कमजोर होती जा रही है, शेयर मार्केट में मंदी छाई है। देश भुखमरी के कगार पर खड़ा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। केन्द्र सरकार अस्थिरता की डावांडोल स्थिति में है, ऐसे समय में पहाड़ों पर बसा ये प्रदेश जिस गति से उन्नति कर रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाये कम है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में एक कार्यकाल के चार वर्षो में 64 कीर्तिमान स्थापित कर विभिन्न संस्थाओं, एनजीओ, वृत्तपत्र समूह, विदेशी संस्थाओं, केन्द्र सरकार-सभी की नजरों में हिमाचल आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। केवल चुनावी वादे पूरे करने तक दायरा सीमित ना रखकर वायदों से बढ़कर आम आदमी की बेहतरी तथा प्रदेश का विकास तेज गति से करने का काम भाजपा शासित हिमाचल प्रदेश में हो रहा है।

विभिन्न प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा राज्यों के परफॉर्मेंस पर किये गये सर्वेक्षणों में बेस्ट परफार्मिंग स्टेट के रूप में हिमाचल उभरा है। 'इंडिया टुडे' के स्टेट ऑफ स्टेट्स सर्वेक्षण में 'ओवर ऑल परफारमेंस' के लिये 'बेस्ट बिग स्टेट' उभर कर आया है। शिक्षा, पर्यावरण, मेक्रो-इकॉनामी, निवेश, हाउसिंग डेवलपमेंट जैसे विकास सूचकों में भी हिमाचल धूमलजी के नेतृत्व में प्रथम स्थान पर रहा है।

कृषि, ढांचागत विकास व उपभोक्ता बाजार में भी हिमाचल श्रेष्ठ पाया गया है। 'एग्रीकल्चर टुडे' पत्रिका द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई पहल व बेहतर कार्य करने के लिये ''स्टेट एग्रीकल्चर लीडरशिप एवार्ड- 2010' से सम्मानित किया गया है।

देश विदेश के टूरिस्टों के लिए आकर्षण

केन्द्र बना हिमाचल दिन-प्रतिदिन टूरिस्टों का पसंदीदा गंतव्य स्थल बनकर उभर रहा है- ''बेस्ट ट्रेवल डेस्टीनेशन'' तथा शिमला को ''बेस्ट माउंटेन/हिल स्टेशन नवाजा गया है।

पर्यावरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर प्रदेश सरकार ने हिमाचल को प्रदूषण मुक्त-देवभूमि बनाने का संकल्प पूरा किया है। आईबीएम-7 व 'आउटलुक' पत्रिका द्वारा किये सर्वेक्षण में महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा पर्यावरण संरक्षण के

लिये 'डायमंड स्टेट अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। एक दूसरे सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ओवरऑल परफॉरमेंस, पूंजी निवेश व मेक्रोइकोनोमी में फास्टेस्ट मूवर स्टेट से नवाजा गया है।

यह सभी कीर्तिमान सरकार की जनाभिमुख नीति व आम आदमी के विकास की ओर प्रतिबद्धता दर्शाते हैं।

'सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य' इस मुद्दे पर यह पहाड़ी प्रदेश स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय संकल्पना को साकार कर समाज के अंतिम व्यक्ति के सुख समृद्धि में बढ़ावा देकर उनके जीवनमान में आमूल परिवर्तन का सपना लेकर प्रो. प्रेम कुमार धूमल और उनकी कार्यक्षम टीम काम कर रही है।

'अटल स्वास्थ्य सेवा' जैसी अद्भुत कल्पना उन्होंने अपने शासन द्वारा सही कर बताई है। समाज का कोई भी घटक 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकता है और तुरंत सरकारी अस्पताल में दवा और ईलाज की व्यवस्था होती है। यह क्रियान्वयन कर आम आदमी की चिंता करने वाला हिमाचल अपने आप में एक मिसाल के तौर पर उभरा है।

केरल को पीछे छोड़ कर नंबर एक साक्षर स्टेट बना हिमाचल अब 'शिक्षा का हब' बनने जा रहा है, उच्चस्तरीय नये पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को प्रारम्भ कर उच्च शिक्षा के गुणवत्ता के साथ-साथ बाहर के विद्यार्थियों को आकर्षित करना और प्रदेश की जनता को रोजगार उपलब्ध कराना, व्यापार बढ़ाना, ऐसे दूरदर्शी कार्य इसी सरकार की देन है। विशेषकर प्रोफेशनल व तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रदेश के छात्रों को बाहर जाने से रोकने में भी सरकार यशस्वी रही है।

'दीनदयाल किसान बागवान' योजना का रूप कृषि पैदावार में विविधता लाकर 'कृषि आर्थिकी' को बढ़ाना व नये रोजगार का सृजन सरकार ने बखूबी किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन का ध्यान रखकर 300 करोड़ रुपये की लागत से दूधगंगा योजनाओं ने भी मूर्तरूप लिया है। 'एपल रिप्लान्टेशन प्रोजेक्ट' के माध्यम से सेब के लिये प्रसिद्ध हिमाचल ने पुराने पेड़ जिनकी पैदावार कम हो गई उसमें गुणवत्ता वृद्धि व अधिक पैदावार के प्रयास किये हैं।

'पारदर्शी व संवेदनशील प्रशासन' का ध्येय लेकर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये हिमाचल सरकार ने 'ई-गर्वनेंस' प्रचलित कर व 'प्रशासन जनता के द्वार' शिविर आयोजित कर निश्चय ही विशेष पहल की है। 'हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय' विधेयक जनता को न्याय दिलवाने की उल्लेखनीय पहल है।

'पॉलीहाउस निर्माण' योजना के तहत हिमाचल सरकार ने 8740 पॉलीहाउस बनाकर एक बड़े क्षेत्र को संरक्षित खेती के अधीन किया है।

स्वरोजगार स्वावलंबन एवं स्वाभिमान का ध्येय रखकर सरकार ने योजनाएं बनाई, बजट में प्रावधान किया, प्रशासन यंत्र में सुधार किए-तो क्या चमत्कार हो सकता है इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश हैं।

'सबका हित सबका कल्याण' ध्येय रखने वाले प्रो. धूमल ने प्रगति व जनकल्याण का नया अध्याय रचकर समाज के हर वर्ग को लाभान्वित किया है।

प्रो. धूमल से एक साक्षात्कार के मध्य जब यह प्रश्न रखा कि आपने इतने कीर्तिमान स्थापित करने व उच्चतम सफलता प्राप्त करने के पीछे क्या घटक हैं व आप इसका श्रेय किसको देते हैं- एक तो उन्होंने अपने सरल उत्तर में कहा- ''मैं इसे ईश्वर की पा अपने सहयोगियों की क्षमता व जनता का प्रेम मानता हूं।''

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रिय प्रदेश हिमाचल आने वाले दिनों में और भी तरक्की कर देश के विकास में अपना योगदान देगा- ऐसी आशा है। निश्चित रूप से प्रगति, विकास व जनहित के पथ पर हिमाचल सभी प्रदेशों के लिये अनुकरणीय रहेगा। ''हिमाचल प्रदेश सरकार भाजपा की सफलता की पहचान है'' और ''शिखरों को छूता हिमाचल पूरे देश की शान है।'' ■

# आंकड़ों से नहीं आंखों से देखो गरीबी को

✍ संजीव कुमार सिन्हा

*''मेरे सपने का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन आवश्यकताओं का उपभोग राजा और अमीर लोग करते हैं, वही गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिए, इसमें फर्क के लिए स्थान नहीं हो सकता। गरीबों को जीवन की सामान्य सुविधाएं अवश्य मिलनी चाहिए, जिनका उपभोग अमीर आदमी करता है। मुझे इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि हमारा स्वराज्य तब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं होगा, जब तक वह गरीबों को भारी सुविधाएं देने की पूरी व्यवस्था नहीं कर देता।''*

**–महात्मा गांधी**

एक हिंदी फिल्म का मशहूर संवाद है :'तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख....पर इंसाफ नहीं होता माई लॉर्ड!' इसी तर्ज पर यह कहा जा सकता है : 'कमिटी पर कमिटी, कमिटी पर कमिटी, कमिटी पर कमिटी....पर गरीबी रेखा की परिभाषा तय नहीं होती।'

'गरीबी' एक बार फिर सुर्खियों में है। योजना आयोग के अनुसार, अब शहर में 28 रुपए 65 पैसे प्रतिदिन और गांवों में 22 रुपए 42 पैसे खर्च करनेवाले को गरीब नहीं कहा जा सकता। आयोग के इस निष्कर्ष पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया। संसद में भी विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। सांसदों ने कहा कि योजना आयोग में ऐसे व्यक्तियों को बैठाया गया है जो गरीबों की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। माहौल को भांपते हुए केंद्र सरकार ने फिर से गरीबी रेखा पर विचार करने की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें गरीबी को मापने के लिए एक बहुआयामी तरीका अपनाना होगा। पिछले वर्ष भी योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर कर कहा था कि यदि शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपए कमाता है और गांव में रहनेवाला प्रतिदिन 26 रुपए तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि अगली बार वह प्रामाणिक आंकड़े लेकर आए।

कांग्रेसनीत यूपीए शासन में गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए कई बार समितियां बनाई गई। लेकिन हर बार नतीजा ढाक के तीन पात ही रहा। गरीबी रेखा के साथ बार-बार छेड़खानी की जा रही है। परंतु इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई। एक के बाद एक समितियों का गठन होता है जो एक दूसरे की रिपोर्ट को काटते हैं वहीं योजना आयोग भी बार-बार अपने आकलन से गरीबों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आती। ये आंकड़े इतने भ्रमित करने वाले हैं कि इसे जानकर किसी का भी सिर चकराने लगेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इन सारी कवायदों पर जनता की गाढ़ी कमाई यूं ही लुटाई जा रही है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सरकार गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप देती है।

### क्या है गरीबी रेखा?

**किसी देश में एक उचित जीवन स्तर जीने के लिए जरूरी न्यूनतम आय को गरीबी-रेखा कहा जाता है। इसकी शुरूआत 1970 के दशक में हुई थी। उस समय गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक घर में भोजन की खपत को इसका आधार बनाया था। बाद में तेन्दुलकर समिति की रिपोर्ट ने यह अवधारणा प्रस्तुत किया कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता गरीबी रेखा तय करती है।**

आइए, एक नजर डालते हैं इन रिपोर्टों के निष्कर्षों पर –

- योजना आयोग ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के तथ्यों के आधार पर देश में 27 फीसदी गरीबी का आकलन किया।
- सुरेश तेंदुलकर समिति ने आबादी के 37 फीसदी हिस्से को गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में रखा।
- अर्जुन सेनगुप्ता समिति ने कहा कि लगभग 77 फीसदी लोग गरीब हैं और ये मात्र 20 रुपए प्रतिदिन पर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं।
- एन सी सक्सेना समिति ने देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे माना है।

यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि भारत किस ओर जा रहा है? भारत के सुपर पावर बनने का सपना कैसे साकार होगा? 'विजन 2020' का सपना कैसे पूरा हो सकेगा? कांग्रेस पार्टी भी बार-बार 'विजन 2020' को लेकर दस्तावेज जारी करती है, क्या उसके कोई मायने हैं? कांग्रेस को लगभग पांच दशकों तक केन्द्र में रहने का अवसर मिला

है लेकिन उसने गरीबी मिटाने की दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए लेकिन एक काम उसने बार-बार किया- गरीबों की संख्या को कम दिखाने के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किए। गरीबी से कांग्रेस का पुराना रिश्ता है। भारत में गरीब बहुसंख्यक हैं इसलिए कांग्रेस उसे वोट बैंक की नजर से देखती है। विदित हो कि सन् 1971 के लोकसभा चुनाव के पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा उछाला था और जनता इस लोक-लुभावन नारे में फंसी थी। उसने कांग्रेस का साथ दिया। पार्टी सत्ता में भी आई लेकिन उसने गरीबों की सुध नहीं ली।

केन्द्र सरकार दावा करती है देश में गरीबी कम हुई है। गत 19 मार्च 2012 को योजना आयोग ने गरीबी का जो आकलन जारी किया उसके अनुसार 2004-05 से 2009-10 के बीच गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या 37.2 प्रतिशत से घटकर 29.8 प्रतिशत हो गया। यानी 7.4 प्रतिशत की कमी। इनमें ग्रामीण क्षेत्र में 41.8 प्रतिशत से घटकर 33.8 प्रतिशत यानी 8 प्रतिशत तथा शहरों में 25.7 प्रतिशत से 20.9 प्रतिशत यानी 4.8 प्रतिशत की कमी आई।

भारत की आजादी के 65 साल बाद भी गरीबी एक प्रमुख चुनौती है। यह महज चुनौती नहीं अपितु अभिशाप है। देश की आधी आबादी भूखे पेट सोने पर अभिशप्त हैं वहीं भंडारण की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण हर साल 7 प्रतिशत अनाज सड़ जाता है। क्या 20 रुपए, 22 रुपए, 26 रुपए, 28 रुपए और 32 रुपए में आज के बेलगाम महंगाई के दौर में कोई ठीक से जीवन-यापन कर सकता है? क्या वह इतने में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? तो फिर इन्हें सरकार किस आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर बता रही है? पहले कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' के झूठे नारे दिए। गरीबों को बरगलाया। उनके वोट हथियाए। और सत्ता में आने पर उन्हें ठेंगा दिखा दिया। तो बाद में गरीबों ने भी इसका कांग्रेस से बदला लिया। केन्द्रीय सत्ता पर अपना एकाधिकार मान चुकी कांग्रेस को सत्ताच्युत होना पड़ा। कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा। और इस पार्टी ने फिर गरीबों को ठगने का इरादा बनाया। इस बार इसने अपना नारा बदला। 'गरीबी हटाओ' की जगह 'आम आदमी का हाथ-कांग्रेस के साथ' किया। अब कांग्रेस का यह हाथ गरीबों की जेब से होते हुए गले तक पहुंच गया है। आज आम आदमी को दो वक्त का भोजन जुटाने में पसीने छूट रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें सुरसा की मुंह की भांति बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में आग लगी हुई है। और ऐसे में बार-बार गरीब रेखा का खेल खेलकर सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे योजनाकार सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ठोस आकलन करें। भारत कृषि प्रधान देश है। 62 प्रतिशत लोगों की आजीविका का साधन है कृषि। आज भी 60 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर है। हालात इस कदर भयावह हो गए हैं कि समुचित सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण देश के 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ने का मन बना चुके हैं। यह स्पष्ट है कि यदि देश से गरीबी का कलंक मिटाना है तो कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत में जो विकास का मॉडल है उसमें धनी वर्ग का हित ज्यादा सधता है। आम आदमी की उपेक्षा की जाती है। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कॉरपोरेट घराने की चिंता करती है जबकि छोटे-छोटे उद्योगों की हालत चिंताजनक है। इस दिशा में भी गंभीरता से सोचे जाने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक हाथों को रोजगार मिले। ■

## चौंकाने वाले आंकड़े

- देश की करीब 32 प्रतिशत आबादी गरीब है।
- विश्व बैंक के मुताबिक 41.6 फीसदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे हैं।
- ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलेपमेंट इनिशिएटिव ने 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलेपमेंट प्रोग्राम के लिए मल्टी डाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स तैयार किया, जिसमें बताया गया है कि 53.7 प्रतिशत भारतीय लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।
- 2005 में वर्ल्ड बैंक ने क्रय शक्ति के आधार पर भारत में गरीबों की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा बताया था।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक भारत की आधी आबादी गरीब है।
- यूनडीपी की मल्टीडायमेंशनल गरीबी सूचकांक के मुताबिक भारत की कुल आबादी में 55 फीसद लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- योजना आयोग के अनुसार, 42.3 प्रतिशत दलित और 47.4 प्रतिशत आदिवासी गरीब है।
- संप्रग सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने गरीबी अनुपात का आंकड़ा 46 फीसदी रखे जाने की सिफारिश की है।
- यह अनुमान भी लगाया गया है कि दुनिया की निर्धन आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा भारत में है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने अपने 66वें परिवार उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण में कहा है कि गांवों में लोग औसत 1054 रुपए 10 पैसे एवं शहरों में 66 रुपए 10 पैसे बैठता है। इसके अनुसार गांवों में 64.47 प्रतिशत एवं शहरों में 66.70 प्रतिशत यानी कुल आबादी का करीब 65 प्रतिशत गरीबी की परिधि में आ जाएंगे। इससे करीब 78 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगी।
- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत बहुत पीछे है और 169 देशों की सूची में भारत का क्रम 119 वें स्थान पर आता है।

# भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार

✍ राम प्रसाद त्रिपाठी

आज जबकि एक बेमिसाल स्तर पर कुशासन का बोलबाला है तो लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री ईमानदार है? क्या आज की यह सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है? क्या प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के खिलाफ लग रहे गम्भीर कदाचारण व्यवहारों के आरोपों को जानते तक नहीं? क्या प्रधानमंत्री अपने ही मंत्रियों और सरकार के आचरण और चरित्र पर उठे सवालों से स्वयं को मुक्त रख सकते हैं? इसके विपरीत, कुछ स्वयंभू बुद्धिजीवी तथा तथाकथित सेक्युलर मीडिया इस तथ्य पर अपने ऐसे निष्कर्ष निकालते रहते हैं कि मनमोहन सिंह ईमानदार व्यक्ति हैं, फिर भी संभव है कि उनकी मंत्रिपरिषद के लोगों की संदिग्धता हो सकती है।

यदि हम शांतभाव से विश्लेषण करें तो कुछ मौलिक प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे, क्या यह सम्भव है कि जो व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं द्वारा फटकारे जाने के बाद भी उन अत्यंत भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब यही निकलता है कि वह अपनी ही नाक के नीचे चल रहे घपले, घोटालों की उपेक्षा करते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों की उपेक्षा करता है और वह भ्रष्टाचार और कालेधन के संकट की तरफ से मुंह फेर लेता है और फिर भी वह ईमानदार और निष्ठावान होने का दावा करता है। यह कहना भी जरूरी है कि औसत भारतीय उच्चतम पद पर बैठे प्रधानमंत्री द्वारा अपनी जिम्मेदारी त्याग देने से किसी तरह खुश नहीं हो सकता है क्योंकि उसके सम्बन्ध में तो माना जाता है कि वह ही सरकार के पीछे बड़ी ताकत है। हाल ही में, अनेक संवैधानिक संस्थाओं- सीएजी की रिपोर्टों, सुप्रीम कोर्ट के अधिनिर्णयों और टिप्पणियों में कांग्रेस-नीत यूपीए-II सरकार के कई मंत्रियों के नाम घसीटे गए हैं जिनमें पी. चिदम्बरम, एस.एम. कृष्णा, शरद पवार, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, विलासराव देशमुख, वीरभद्र सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, एस.के. शिंदे जैसे वरिष्ठ मंत्रीगण और स्वयं प्रधानमंत्री शामिल हैं। स्पष्ट है कि उनके संदिग्ध निर्णयों के आचरण तथा त्रुटियों के कारण प्रथम दृष्टया देश के खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जो किसी भी विश्वसनीय तर्क के आधार पर केवल भ्रष्टाचार की श्रेणी में ही कहा जाएगा। सम्भव है कि इनमें से कुछ मंत्री निर्दोष हों, परन्तु प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार ही, जिन्होंने बार-बार अंग्रेजी में कहा है कि "Caesar's wife should be above suspicion" अर्थात् किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को संदेह के दायरे से बाहर रहना चाहिए। परन्तु, भ्रष्टाचार के आरोपों के पहाड़ से घबराई यूपीए सरकार की सोच यही है कि प्रहार करना ही शायद बचाव का सबसे अच्छा साधन है, इसलिए वह किसी भी तरह उच्च पदों की गरिमा बहाल करने के मूड में नहीं है।

आज तो स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि आदर्श हाउसिंग घोटाला में केन्द्रीय मंत्री विलासराव देशमुख न्यायिक आयोग के सामने अपना दोष दूसरे पर मढ़ते हुए कह रहे हैं कि यह सारा दोष तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण का है। उधर, अशोक चव्हाण का मानना है कि आदर्श घोटाले के लिए उनके पूर्व रह चुके मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जिम्मेदार हैं। एक और मामला है जिसमें वाणिज्य मंत्री आनन्द शर्मा ने चावल घोटाले में पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ की खुल कर आलोचना की है और कहा है ''नाथ को चावल घोटाले में शामिल होने के कारण जेल भेजना चाहिए।'' इस प्रकार की गम्भीर त्रुटियों के भ्रष्ट मंत्रियों पर मुकद्दमा चलाए जाने की बजाए कांग्रेस-नीत यूपीए इस प्रकार के निंदनीय कारनामों के लिए बड़े शर्मनाक ढंग से जांच

***'इण्डिया अगेंस्ट करप्शन' टीम द्वारा जारी किए गए हाल के आंकड़ों ने अनेक कांग्रेसी मंत्रियों के संदेहास्पद रिकार्ड की पोल खोल कर रख दी है और सचमुच भारतीय इतिहास में इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार के आघातकारी प्रकरणों ने देश को आक्रोश और निराशा में डाल दिया है। वर्तमान नीतिगत अपंगता और आर्थिक संकट को देखते हुए कम से कम इतनी तो उम्मीद की ही जाती थी कि कुछ न कुछ गवर्नेंस जैसी कोई बात तो सामने आएगी, परन्तु यूपीए ऐसा कुछ भी करने में बुरी तरह से विफल रही है।***

एजेंसियों का दुरूपयोग करके इन पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहां तक कि सिविल सोसाइटी समूहों और लोगों को, जो भ्रष्ट और कालेधन के कार्यों के लिए दण्ड दिलाने की कोशिश करते हुए, उन्हें भी चुन-चुन कर निशाना बनाया जाता है। सम्भवत: इन परिस्थितियों में भ्रष्टाचार-विरोधी निकायों के परिणामों को देखते हुए मजबूत लोकपाल जैसी संस्थाओं के गठन को अनंत काल तक के लिए टाल दिया गया है। यहां तक कि विदेशों में कालाधन जमा कराने वालों के नाम भी सहज ही छुपा लिए जाते हैं। इन सभी बातों से भ्रष्टाचार के संकट की विशालता का पता चलता है, जिससे यूपीए-II सरकार को नैतिक तंत्र टूट कर रह गया है।

सरकार का चाहे जो भी दावा हो, परन्तु कांग्रेस-नीत यूपीए के अब तक गुजर चुके 38 महीनों का कार्यकाल की आभा धीरे-धीरे खत्म होती चली जा रही है, जिसमें न केवल आर्थिक मोर्चे पर उसकी कार्यकुशलता कहीं दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि महंगाई बढ़ी है, बल्कि स्वतंत्रता काल के बाद अब तक देखा जाए तो यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के प्रति इतनी उपेक्षा पहले किसी सरकार ने नहीं की जिससे उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है।

'इण्डिया अगेंस्ट करप्शन' टीम द्वारा जारी किए गए हाल के आंकड़ों ने अनेक कांग्रेसी मंत्रियों के संदेहास्पद रिकार्ड की पोल खोल कर रख दी है और सचमुच भारतीय इतिहास में इस तरह की मिसाल देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार के आघातकारी प्रकरणों ने देश को आक्रोश और निराशा में डाल दिया है। वर्तमान नीतिगत अपंगता और आर्थिक संकट को देखते हुए कम से कम इतनी तो उम्मीद की ही जाती थी कि कुछ न कुछ गवर्नेंस जैसी कोई बात तो सामने आएगी, परन्तु यूपीए ऐसा कुछ भी करने में बुरी तरह से विफल रही है।

हताश देश किसी भी तरह से वर्तमान कांग्रेस-नीत यूपीए-II की दक्षहीनता और भ्रष्ट सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और ऐसा लगता है कि वह समय दूर नहीं है जब लोग इस भ्रष्ट और निष्क्रिय सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। ■

# यूपीए-II कार्यकाल में कांग्रेस मंत्रियों के घोटालों की कुछ गाथाएं

**कोयला ब्लाक घोटाला**

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह नवम्बर 2006 से मई 2009 तक स्वयं कोयला मंत्रालय का प्रभार संभाले थे। उनकी निगरानी में एक बड़ा कोयला आवंटन घोटाला सामने आया, जिसमें प्राइवेट फर्मों को खूब लाभ कमाने की अनुमति दी गई, जो इस बात से स्पष्ट है कि अब इन्हें सरकारी क्षेत्र में रखा गया है और सीएजी की रिपोर्ट है।

**2-जी घोटाला**

वित्त मंत्री के रूप में पी. चिदम्बरम ने अपने ही मंत्रालय के अधिकारियों की बात को नकारा, जिन्होंने स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात कही थी और इसकी बजाए उन्होंने 2-जी घोटाला होने दिया। यह भी ध्यान देने की बात है कि सीबीआई ने स्पेक्ट्रम की कम कीमत रखने पर ए. राजा को चार्ज-शीट दी है। पी. चिदम्बरम भी इसके लिए उतने ही दोषी हैं। 2010 में पेश अपनी रिपोर्ट में सीएजी का अनुमान है कि इससे सरकार के खजाने को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।

**चावल-निर्यात घोटाला**

अक्टूबर 2007 में जब कमलनाथ वाणिज्य मंत्री थे तो कांग्रेस-नीत केन्द्र सरकार ने बासमती चावल को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। यह निर्णय इसलिए लिया गया ताकि देश की मुद्रास्फीति कम हो सके। इस दौरान, यह देखने में आया कि केबिनेट मंत्री ने कुछ चुनिंदा प्राइवेट कम्पनियों को अनुमति देकर इस प्रतिबन्ध को चकमा देने में मदद की, जिससे देश के खजाने को 2500 करोड़ रूपए का भारी चूना लगाया।

**आदर्श सोसाइटी घोटाला**

दो वर्तमान केन्द्रीय केबिनेट मंत्री विलसराव देशमुख और एस.के. शिंदे तथा महाराष्ट्र के एक पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुम्बई में आदर्श को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछेक पार्टियों के साथ पक्षपात का आरोप है, जो मूलत: कारगिल में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए बनी थी।

**हिमाचल में अवैध भर्ती/तैनाती घोटाला**

जब हिमाचल प्रदेश में 1993 से 1998 तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, तब 'चिट सिस्टम' के जरिए उनकी सरकार ने औपचारिक रूप से भर्ती और तैनाती की गई। 1998 में, इस आरोप की जांच के लिए दो समितियां बनाई गईं। 1999 की अपनी रिपोर्ट में, समिति ने श्री सिंह और उनके मंत्रियों के खिलाफ इस आरोप को सही पाया।

**सीडब्ल्यूजी घोटाला**

इस घोटाले का सम्बन्ध दिल्ली में कामनवेल्थ खेल 2010 के आयोजन से जुड़ा है जिसका आयोजन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और आईओए के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के नेतृत्व में किया गया था। 70,000 करोड़ रूपए के घोटाले का यह घोटाला कामनवेल्थ खेलों के दौरान ही उभर कर आया और श्री कलमाड़ी तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और कामनवेल्थ खेलों पर सीएजी रिपोर्ट में इस घोटाले में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हितकारियों की सूची में रखा गया है।

# निकाय चुनाव में बही कमल की बयार

& loknnkrk }kjk

mत्तर प्रदेश की जनता ने स्थानीय निकाय चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा के कमल को खिलाया है। कुल 12 में से 10 नगर निगमों एवं 600 से ज्यादा नगरपालिकाओं, पंचायतों में भाजपा को मिली जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि जहां लोग महज 100 दिन में ही सपा के गुंडाराज से त्रस्त हो गए हैं वहीं यह कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के घोटालों के खिलाफ यह स्पष्ट जनादेश है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस जीत पर वक्तव्य जारी कर कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और इससे पूर्व दिल्ली नगर निगम, महाराष्ट्र स्थानीय निकाय और अब उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी विजय पताका फहरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि कुशासन के खात्मे के लिए पार्टी कार्यकर्ता आम जनता भाजपा को एकमात्र विकल्प के रुप में स्वीकार कर चुकी है और कांग्रेस व उसके कुशासन को बाहर एवं अंदर से समर्थन दे रही पार्टियों को सबक सिखाना शुरु कर दिया है।

**प्रदेश भर में जश्न का माहौल**

नगर निकाय चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप्त हुआ है। अधिकतर नगर निकायों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में पार्टी की जीत से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे हैं। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने ढोल और नगाड़ों के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई का स्वागत किया तथा मिठाई का वितरण किया।



**सपा सरकार का हनीमून 110 दिनों में समाप्त : डॉ. बाजपेई**

भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली भारी सफलता को जनता की जीत बताया। गत 7 जुलाई को प्रदेश कार्यालय पर स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रेस और मीडिया के लोगों से व्यक्त करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेई ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों में मिली सफलता से हमें चुनौतियों से लड़ने का साहस और विश्वास मिला है। चुनाव परिणाम से जनसरोकारों के प्रति संघर्ष की क्षमता में वृद्धि होगी।

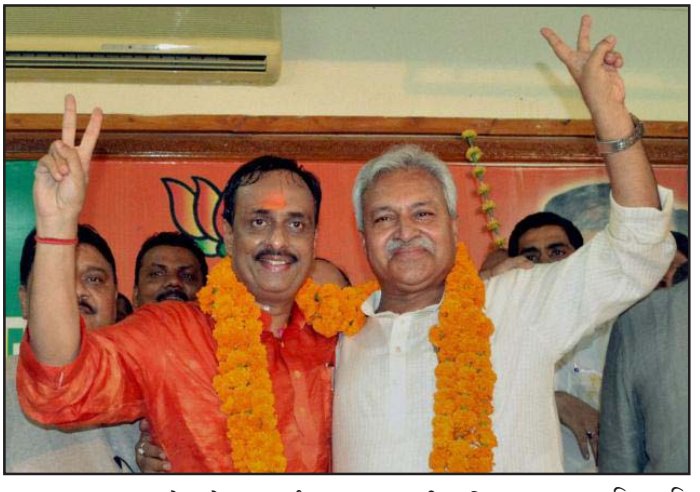

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद अकेले भाजपा ने पार्टी के चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों के बल पर चुनाव लड़ा है। जबकि कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपने सिम्बल पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सकी।

सपा व बसपा तो अपने सिम्बल पर चुनाव मैदान में उतर ही नहीं सकी। अब हैलीकॉप्टर, भगौना, तराजु जैसे चुनाव चिह्नों पर अपने प्रत्याशी उतारे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी सरकार का सामान्य जनता के साथ हनीमून कुल 110 दिनों में समाप्त हो गया। जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी के लोक लुभावन छलावे से उठ गया।

भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव परिणामों मे प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसका श्रेय पार्टी के सामूहिक नेतृत्व को देते हुए कहा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, विनय कटियार, मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय सचिव वरूण गांधी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, डॉ. रमापतिराम त्रिपाठी, सूर्यप्रताप शाही, वरिष्ठ नेता लालजी टण्डन तथा प्रदेश के सभी नेताओं को दिया तथा कहा कि इनके अभुतपूर्व सहयोग व प्रयास से हम यह चुनाव जीत सके है।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी को मिली भारी सफलता के लिए प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी है तथा कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सपा बसपा की नाकामी और भ्रष्टाचार के कुनबे को नकार दिया है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2014 में केन्द्र में एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें उत्तर प्रदेश की मजबूत भूमिका होगी। ■

# देश में भुखमरी, गरीबी, मंहगाई, किसान आत्महत्या कांग्रेस सरकार के पापों का परिणाम – नितिन गडकरी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉ. साहिब सिंह वर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर 30 जून को नई दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में व्याप्त भुखमरी, गरीबी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या कांग्रेस सरकार का पाप है। भारत एक अमीर देश है लेकिन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों, घोटालों और भ्रष्टाचारों के कारण यहां की जनसंख्या गरीब है।

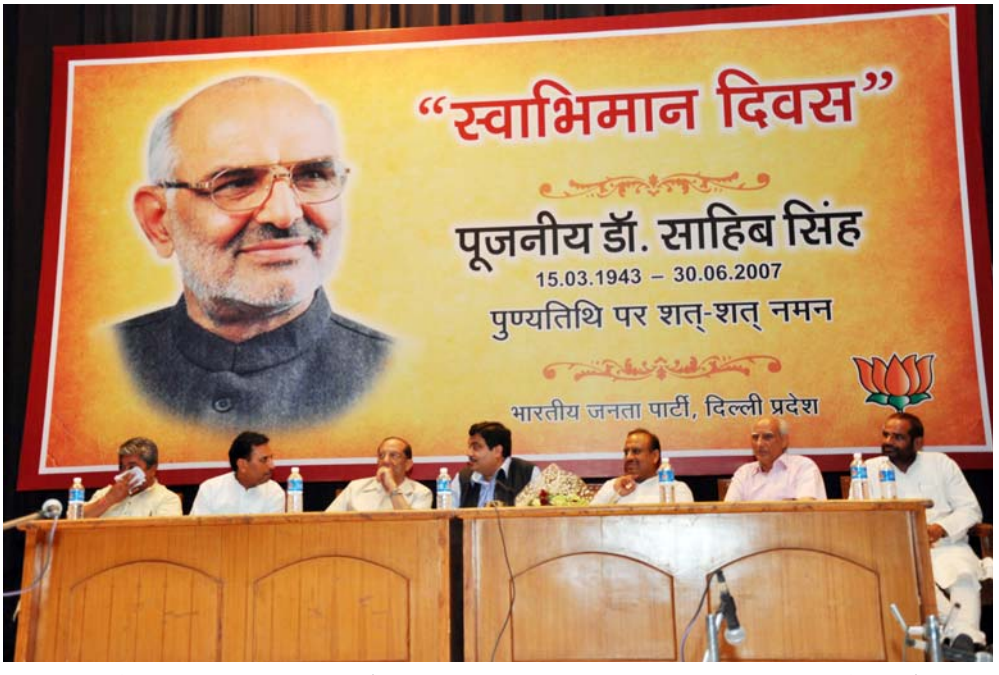


इस स्थिति को भाजपा ही बदलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि दिल्ली के लोग डॉ. साहिब सिंह वर्मा के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ें। श्री वर्मा जमीन से जुड़े एक महान सोच वाले नेता थे। उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय दर्शन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया था। इसी को पूरा करने में उन्होंने अपना सारा जीवन खपा दिया। कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्रद्धांजलि सभा मावलंकर हॉल में आयोजित थी। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की। उन्होंने सभागार में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि डॉ. वर्मा ने देश के 40 करोड़ असंगठित मजदूरों, बाल श्रमिकों के सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। केन्द्र में श्रम मंत्री होने के दौरान उन्होंने इन असंगठित मजदूरों के पेंशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बिल पेश किया था। सरकार बदली और वह बिल कांग्रेस सरकार ने बट्टे खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. वर्मा एक कुशल संगठक, प्रशासक कार्यकर्ता तथा मित्र के समान नेता थे। जिनकी क्षतिपूर्ति असम्भव है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने कहा कि डॉ. वर्मा का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे चाहते थे कि देश के हर गरीब की दशा और दिशा बदले। भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और समृद्ध बने। उनकी डायरी में असम्भव जैसा कोई शब्द था ही नहीं।

उन्होंने खेलों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। दिल्ली में मेट्रो उन्हीं की विशाल सोच की देन है। वे शहीदों का स्मारक बनाकर देश की भावी पीढ़ी को उनके जैसे बनाने का स्वप्न देखते थे। इसे उन्होंने पूरा भी किया।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा ने कहा कि डॉ. वर्मा समय के अनुसार अपनी भूमिका स्वयं तय करते थे। उन्होंने अनेक असम्भव कार्यों को सम्भव बनाया। उन्होंने डॉ. वर्मा की याद में एक शेर पढ़ा 'जिंदगी के सफर में कुछ इस तरह चल मेरे अजीज – जब तू साथ न चल सके तब तेरी याद साथ-साथ चले'। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मन्त्री कैप्टन अभिमन्यु, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम तथा प्रदेश महामंत्री रमेश बिधूड़ी सहित महापौर, विधायक, उपमहापौर, पार्षद, जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी तथा पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

श्रद्धांजलि सभा की शुरूआत राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्जवलन से हुई। डॉ. वर्मा के जीवन प्रसंगों से सम्बन्धित एक जीवंत चलचित्र का प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया गया। ■

# निजी एवं स्वयंसेवी क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोकने हेतु विधेयक की जरूरत

भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा 7 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में विदेशी बैंकों से भारतीय धन वापिस लाने हेतु नयी पहल के अन्तर्गत फ्लोटिंग वारंट अवधारणा तथा निजी एवं एनजीओ क्षेत्र में घूसखोरी रोधी विधेयक पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल अग्रवाल ने घोषणा की कि आगामी सत्र में लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा एक निजी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। इससे पूर्व भाजपा सांसद श्री प्रकाश जावडेकर के द्वारा एक निजी विधेयक राज्य सभा में लाया जा चुका है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं मुख्य प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने, कहा कि सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच में सांठगांठ से राष्ट्रीय संसाधनों को मनमाने तौर पर लूटा जा रहा है। 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाले की चर्चा करते हुये कहा कि सरकार ने वेबसाइट पर केवल 45 मिनट का समय देकर 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति अपनाते हुये करोड़ों रुपयों की शर्मनाक तरीके से हेरा-फेरी की। पर जनता कभी भी भ्रष्ट नेताओं को माफ़ नहीं करती है। उन्होंने याद दिलाते हुये कहा कि राजीव गांधी को तीन चौथाई बहुमत देने वाली कांग्रेस-सरकार को जनता ने बोफोर्स कांड के चलते अगले चुनावों में अल्पमत में ला दिया। श्री प्रसाद ने कहा कि जो लालू प्रसाद जातिवाद के दमपर दशकों सत्ता का सुख भोगने की सोच रहे थे, वही चारा घोटाला के चलते सत्ता से बाहर कर दिये गये।

इस कार्यक्रम में बोलते हुये प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्री सी राजशेखर ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार आज एक ज्वलन्त मुद्दा है, जिससे आम आदमी का विश्वास टूट रहा है। भाजपा, आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री गोपाल अग्रवाल ने फ्लोटिंग वारंट अवधारणा को स्पष्ट करते हुये कहा कि करचोरी के पनहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टेक्स हैवन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोर्चे पर सूचना के आदान प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। हम एक ऐसे 'फ्लोटिंग वारंट' अवधारणा की मांग करते है जैसे कि अमेरिका में 'जॉन डो लॉसूट' के नाम से प्रसिद्ध है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी कर सकते है। और इस वारंट के आधार पर विदेश में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते है उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्त्वपर्ण पहलू यह है कि भ्रष्ट कारोबारी वर्ग, रियल एस्टेट डेवलपर, भ्रष्ट नेता, नौकरशाह और इनके बीच सांठ-गांठ होने से रोका जाए, जिससे काला धन पैदा न हो सके। अन्यथा आने वाले समय में इससे हमारी अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित समस्या पैदा होगी।

भ्रष्टाचार एवं कालेधन के कई आयाम हैं, जिसमें महत्त्वपूर्ण पहलू है इसका सृजन। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी हमारी भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली में कई खामियां पाई हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठेके और लाइसेंस आदि के मूल्यांकन के संबंध में तीसरे पक्ष के जरिए तुष्टिकरण और घुसखोरी, सरकारी नीतियों पर चर्चा के जरिए लामबंदी एवं निजी क्षेत्र द्वारा घूसखोरी पर अंकुश लगाने के संबध में हमारे कानूनी प्रावधानों में भी खामियां हैं। इन मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमने निजी क्षेत्र एवं एनजीओ क्षेत्र में घुसखोरी रोधी विधेयक के रूप में विशेष कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इन्हें लागू करने की हमारी पुरजोर मांग है।

सांसद श्री हंसराज अहीर ने आरोप लगाया कि कुछ निजी कंपनियों का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने 'पहल आओ पहले पाओ' नीति स्वीकार की थी। नीलामी प्रक्रिया में करीब दो साल की देरी हुयी। 156 कंपनियों का आवंटन उचित नहीं था क्योंकि

उन्होंने अच्छी राशि लेकर ब्लॉकों का संचालन अन्य कंपनियों को सौंप दिया। जिन कंपनियों को कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया गया उन्होंने खुद उत्पादन शुरु नहीं किया और इसका संचालन अन्य कंपनियों को सौंप दिया तथा मुनाफा कमाया। अहीर ने कहा कि 51 लाख करोड़ रुपये मूल्य का 1700 करोड़ मीट्रिक टन कोयला कंपनियों को लगभग मुफ्त दिया गया। कार्यक्रम के अन्त में जलाधिकार द्वारा पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा गीत 'जिसने भी संकल्प लिया उसने ही इतिहास रचा है' प्रस्तुत किया गया।

इस सभा में 400 से अधिक आर्थिक जगत के गणमान्य व्यक्तियों ने सत्य साईं आडिटोरियम में भाग लिया, जिससे सभी प्रमुख आर्थिक एवं व्यापारिक संगठन जैसे कि एसोचैम, इंस्टीयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट से श्री विनोद जैन, कम्पनी सेक्रेटरी के अध्यक्ष श्री निसार अहमद, पी एच डी चैम्बर आफ कामर्स के श्री विजय मेहता, नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज मेम्बर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री नरेश माहेश्वरी, भारतीय वित्त सलाहकार समिति के श्री अनिल गुप्ता एव श्री अनिल शर्मा ने भी इस विधेयक के समर्थन में अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन श्री ब्रिज सब्बरवाल एव श्री प्रवीण कान्त ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुनील अम्बेकर ने बताया कि इस विधेयक के समर्थन में एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ परिषद ने राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ा हुआ है और आगे इसे और तीव्र गति से बढाएंगे। ■

## 'यूपीए की गलत नीतियों के चलते रुपया हो रहा कंगाल'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केन्द्र सरकार की ''आर्थिक उदारवाद की नीति-अमेरिकी उधारवाद" में बदल गई है जिसके चलते भारत में ''डालर मालामाल और रुपया कंगाल" हो रहा है।

श्री नकवी ने 26 जून, 2012 को नई दिल्ली में "आपातकाल" पर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री देश में आर्थिक चमत्कार की जब-जब तारीख देते हैं, उसके बाद अर्थव्यवस्था और चौपट होती दिखती है, दरअसल अर्थशास्त्रियों की सरकार जमीन शास्त्र से पूरी तरह कट चुकी है, जिसका नतीजा है कि देश सभी संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद आर्थिक दिक्कतों से निजात नहीं पा रहा है ।

श्री नकवी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जिस देश ने भी आत्मनिर्भर अर्थनीति के बजाय अमेरिका निर्भर अर्थनीति के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने की कोशिश की, वह देश इसी प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को औंधे मुंह गिराता रहा। आज भारत में डालर का हर दिन तंदुरुस्त होना और रुपये का बीमार होना सरकार के गलत आर्थिक ताने-बाने का नतीजा है। श्री नकवी ने कहा कि आज अमेरिका तय कर रहा है कि भारत को कच्चा तेल किस देश से लेना है, भारत को सबसे सस्ता तेल बेच रहे ईरान से अमरीकी दबाब के चलते खरीद में भारी कटौती कर दी गई, दुनिया में हर दिन कच्चे तेलों के दाम घट रहे हैं पर भारत में पैट्रोल के दाम आसमान छू रही है। पडोसी बंगला देश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी पेट्रोल की कीमत भारत से आधी है। श्री नकवी ने कहा कि आज देश ''आर्थिक आपातकाल" झेल रहा है, यह आर्थिक आपातकाल आम आदमी के आर्थिक सरोकार पर हमला कर कुछ विदेशी कम्पनियों एवं पूंजीपतियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए है, जिसके चलते महंगाई-बेरोजगारी चरम पर है, मूलभूत विकास का काम ठप्प पड़ गया है। ■

## आपातकाल में जेल में बंद रहे कार्यकर्ताओं को भाजपा ने सम्मानित किया

आपातकाल की 37वीं वर्षगांठ पर 26 जून को भाजपा दिल्ली प्रदेश ने पार्टी कार्यालय में एक समारोह आयोजित करके उस दौरान डीआईआर और मीसा में बंद कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के जुल्मों से कोई सबक नहीं सीखा है। आज भी कांग्रेस का चरित्र तानाशाह का ही है। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस की सरकारें हैं जो आम जनता के हित की चिंता न कर केवल दलालों, माफियाओं, बिचौलियों और मंहगाईखोरों के हितों की सोचती हैं। दिल्ली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यहां की 2 करोड़ जनता भीषण गर्मी में पानी-बिजली बगैर बेहाल है लेकिन मुख्यमंत्री कहती हैं कि दिल्ली में पानी-बिजली की कोई कमी नहीं है। वे बिजली कम्पनियों को दाम बढ़ाने की इजाजत देती हैं भले ही जनता बिजली का बिल न भर सके।

आज का कार्यक्रम भाजपा संस्कृति, बुद्धिजीवी एवं वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री केदारनाथ साहनी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा मुख्यालय प्रभारी प्रो. ओम प्रकाश कोहली, राष्ट्रीय प्रवक्ता तरूण विजय, सुरेन्द्र मोहन लाम्बा, मांगेराम गर्ग, ओम प्रकाश बब्बर, प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि गजेन्द्र सोलंकी, प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री महेश चन्द्र शर्मा पूर्व उपमहापौर एवं भारत गौड़ उपस्थित थे। ■

# स्पैक्ट्रम पर ईजीओएम के प्रमुख के रूप में श्री चिदम्बरम की नियुक्ति निंदनीय ही नहीं दुर्भाग्यपूर्ण भी : भाजपा

***भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 7 जुलाई 2012 को जारी प्रेस वक्तव्य***

2th स्पैक्ट्रम नीलामी और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के लिए मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख के रुप में गृह मंत्री पी. चिदम्बरम की नियुक्ति करने का सरकार का फैसला न केवल निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा 6 जुलाई को हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उनके इस दावे की पोल खोलता है और उसे खोखला साबित करता है कि ''मैंने अपने आचरण में ईमानदारी के उच्च आदर्श को बरकरार रखा है।'' डा. सिंह ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर दी है कि संवैधानिक योग्यता, संसदीय जवाबदेही और शासन प्रणाली में सत्यनिष्ठा जैसे मुद्दे न तो उनके लिए महत्व रखते हैं और न ही उनकी कोई प्रासंगिकता है।

यह बात सभी को मालूम है कि 2 जी स्पेक्ट्रम की कीमत पूर्व दूरसंचार मंत्री श्री ए. राजा ने श्री चिदम्बरम के साथ सलाह करके तय की थी, जो उस समय वित्त मंत्री थे, जिस पर बाद में प्रधानमंत्री ने भी सहमति व्यक्त की थी, इस तथ्य की वह संसद में पुष्टि कर चुके हैं। कुछ अन्य परेशान करने वाले सवाल हैं, जो पूरी तरह से यह साबित करते हैं कि श्री चिदम्बरम को ईजीओएम का प्रमुख बनाना तो दूर वे इसमें शामिल होने के भी हकदार नहीं हैं। ये निम्नलिखित हैं जो सभी के सामने हैं:-

(1) श्री ए. राजा के साथ सहमति व्यक्त करते समय उन्होंने तत्कालीन वित्त सचिव, जो इस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, सहित वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार-बार दी गई इस सलाह की पूरी तरह अनदेखी की कि 2जी स्पेक्ट्रम की कीमत एक जायज बाजार तंत्र के जरिये तय की जानी चाहिए और यह पूरी तरह अनुचित और आपत्तिजनक होगा कि वर्ष 2007-08 में इसे 2001 की दर पर तय किया जाए जब दूरसंचार का काफी तेजी से विस्तार हो गया है।

(2) 2जी मुकदमे में उन्हें सह अभियुक्त बनाने संबंधी दलील पर उच्चतम न्यायालय का फैसला अभी आना बाकी है।

(3) श्री चिदम्बरम ने स्पैक्ट्रम का 2001 की दरों पर आवंटन होने के बाद लाभान्वित होने वाली स्वान और यूनिटैक (मुकदमे का सामना कर रही हैं) जैसी कंपनियों को अपने शेयर बढ़ी हुई कीमत पर बेचने की मंजूरी दी।

(4) न केवल श्री राजा बल्कि 2जी घोटाले में मुकदमे का सामना कर रहे अनेक अन्य अभियुक्त अदालत से श्री चिदम्बरम को बुलाने का आग्रह करते रहे हैं।

(5) मैक्सिस, एयरसेल सौदा, जिसकी इस समय सीबीआई जांच कर रही है, उसमें श्री चिदम्बरम के परिवार के नजदीकी की भूमिका के बारे में निराशाजनक सवाल खड़े हो रहे हैं।

इन स्पष्ट तथ्यों को देखते हुए श्री चिदम्बरम की नियुक्ति न केवल गलत संदेश देती है बल्कि यह हितों के टकराव का स्पष्ट मामला है। यह एक बार फिर इस बात की पुष्टि करता है कि जब कभी भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए (यूपीए में यह सूची अनंत है) डा. मनमोहन सिंह ने कार्रवाई करने की बजाय सभी बातों की अनदेखी की। भाजपा, मीडिया द्वारा छेड़े गए अभियान और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनुभव और शिष्टता का राजनीति और शासन प्रणाली में बेहद महत्वपूर्ण स्थान हैं।

श्री चिदम्बरम को स्पैक्ट्रम पर ईजीओएम का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला कर, प्रधानमंत्री अहंकार के साथ यह बताना चाहते हैं कि उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं है। भाजपा इसका संसद के भीतर और बाहर कड़ा विरोध जारी रखेगी। ■

# प्रादेशिक समाचार

## बिहार

### वोट बैंक की राजनीति कर रही संप्रग सरकार : रविशंकर प्रसाद

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र की संप्रग सरकार कश्मीर के प्रति ईमानदार नहीं है। वह केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देश की प्रतिष्ठा के साथ समझौता कर जनता के समक्ष अपराधी की भूमिका में खड़ी है। देश की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वे 4 जुलाई को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित 'कश्मीर वार्ता की रपट व राष्ट्र की संप्रभुता पर खतरा' विषयक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश सचिव का भारत आने पर पहले उनको हुर्रियत नेताओं से मुलाकात कराना और फिर उनका भारत सरकार से बातचीत होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में आतंकवादी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज जम्मू-कश्मीर के हालात बहुत खराब हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीपी ठाकुर ने कहा कि कश्मीर पर जो रिपोर्ट आई है, उसे जला देनी चाहिए। तीन बड़ी गलतियों के कारण भारत को जम्मू-कश्मीर की समस्या आज भी झेलनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस समस्या का समाधान के लिए ठोस निर्णय लेने की जरूरत है।

संगोष्ठी को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सर्वश्री गिरिराज सिंह, श्रम संसाधन मंत्री जर्नादन सिंह सीग्रीवाल और विधान पार्षद हरेन्द्र प्रताप ने भी संबोधित किया। प्रदेश उपाध्यक्ष संजय मयूख ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि पं. हरिशंकर शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

## झारखंड

### संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रहा यूपीए : गोस्वामी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा है कि केंद्र की यूपीए सरकार दलहित को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है। यूपीए देश हित को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। 2 जुलाई को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित विधि प्रकोष्ठ की कार्यसमिति की बैठक में श्री गोस्वामी ने कहा, यूपीए सरकार में शामिल कांग्रेस सहित अन्य दलों के लोग सामाजिक न्याय का बहाना बनाकर देश के लिए आत्मघाती कदम उठाने को भी तत्पर हो जाते हैं। पिछले वर्षों में कई मौके आए जब न्यायालय के तार्किक निर्णयों को निष्प्रभावी करने के लिए संविधान में संशोधन तक किए गए।

श्री गोस्वामी ने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस द्वारा देशहित का स्थान या तो लुप्त हो गया है या फिर गौण है। कार्यसमिति को प्रदेश महामंत्री बालमुकुंद सहाय व प्रांत संयोजक चंद्र प्रकाश ने भी संबोधित किया। कार्यसमिति में एक प्रस्ताव लाया गया जिसे ध्वनि मत से स्वीकार किया गया।

**कार्यसमिति में पेश प्रस्ताव की खास बातें**

- भाजपा विधि प्रकोष्ठ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा लाए जा रहे एजुकेशन इंस्टीच्यूशन बिल 2010 और नेशनल लॉ स्कूल बिल 2011 का विरोध करता है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार अधिवक्ताओं पर नियंत्रण लगाना चाहती है।
- विधि प्रकोष्ठ राज्य सरकार से मांग करता है कि राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में अधिवक्ताओं में से ही लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, जेपी, एजेपी एवं स्पेशल पीपी को तत्काल बहाल करे।
- अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए गठित एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट अधिवक्ताओं को मेडिक्लेम की स्थिति में पांच लाख की राशि निर्गत करने का प्रावधान सुनिश्चित करे। 30 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुके अधिवक्ताओं को कम से कम 10 लाख रुपये एकमुश्त देने का कदम उठाए।

## हिमाचल प्रदेश

### भाजपा बहुमत से फिर बनाएगी सरकार : सतपाल सत्ती

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर प्रदेश में अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। उन्होंने कहा कि 'मिशन रिपीट' के तहत चंडीगढ़ में योजना बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शाता कुमार उपस्थित रहे। योजना बैठक में आगामी विस चुनावों पर जीत के लिए रणनीति भी बनाई गई और निर्णय लिया गया कि आगामी विस चुनावों में पार्टी की जीत के लिए सभी एकजुटता से कार्य करेगे। प्रदेश भाजपा पूरी तरह से एकजुट है। विस चुनाव में

भाजपा एकजुटता से चुनाव लड़ेगी। भाजपा ने प्रदेश में साढ़े चार वर्ष के दौरान अथाह विकास कराया है। विस चुनाव भी विकास के नाम लड़ा जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी ने कुल्लू के दो दिवसीय दौरे के दौरान कांग्रेसियों को चुनावी टिप्स दिए, जिसका परिणाम आगामी विस चुनावों में कांग्रेस की हार के रूप में नजर आएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में भी राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को चुनावी टिप्स दिए थे, जिसके नतीजे सबके सामने है। श्री सतपाल सत्ती ने कहा कि भाजपा प्रो. धूमल और श्री शांता कुमार के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है जबकि कांग्रेस इस समय प्रदेश में बिखराव की स्थिति में पहुच चुकी है। कांग्रेस में इस समय नेतृत्व की लड़ाई चली हुई है। कांग्रेस नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे है। भाजपा योजनापूर्वक चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में करवाए गए अथाह विकास के नाम पर प्रदेश वासियों से वोट मांगे जाएंगे।

## हरियाणा

### आने वाला समय भाजपा-हजकां का होगा : गुर्जर

गुड़गांव स्थित गीता भवन परिसर में 6 जुलाई को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने सदस्यता अभियान का श्रीगणेश पूनम देवी नामक महिला का फार्म भरकर किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों को कहा कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आने वाला समय भाजपा-हजकां का है। इसके चलते अपनी कमर कस लें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को भाजपा से जोड़ें। प्रदेशाध्यक्ष ने अभियान की शुरुआत पूनम देवी को पार्टी का नया सदस्य तो पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलकराज मल्होत्रा को सक्रिय सदस्य बनाकर की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुके हैं। अब बदलाव का समय है और लोग भाजपा-हजकां गठबंधन से खासी उम्मीद बांधे हुए हैं। इसके चलते हर कार्यकर्ता व पदाधिकारी को सदस्यता अभियान में जुट जाना चाहिए।

## जम्मू-कश्मीर

### डा. मुखर्जी बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित

भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश भाजपा ने जम्मू में 23 जून को अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर खासतौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी भी उपस्थित रहे। डॉ. जोशी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के रिश्ते देश से मजबूत करने के लिए श्रेय देते हुए कहा कि इसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी।

डॉ. जोशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लागू परमिट सिस्टम को तोड़ने के लिए संघर्ष शुरू किया था। आज का दिन प्रदेश भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि राष्ट्र और राष्ट्रीय हित में बंगाल से आकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त समाज के लिए दी थी। डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि देश से प्यार करने वाले हर नागरिक का फर्ज बनता है कि वह डॉ. मुखर्जी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए आत्मचिंतन के साथ काम करें। क्योंकि डॉ. मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान की व्यवस्था के खिलाफ रहते हुए अपनी शहादत होने तक समझौता नहीं किया था।

डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह मन्हास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. निर्मल सिंह, विधायक अशोक खजूरिया, महासचिव सत शर्मा सीए, जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता, डॉ. जितेंद्र सिंह, बाली भगत, कवींद्र गुप्ता, रमेश अरोड़ा, अरुण छिब्बर, असीम गुप्ता, कर्ण सिंह, रमेश शर्मा, जयदीप शर्मा, प्रदुमन सिंह, सुरेंद्र भगत, बलवीर राम आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।

## आंध्र प्रदेश

### किसानों को जल्द बीज उपलब्ध कराए सरकार : किशन रेड्डी

कपास सहित जरूरी बीजों की कालाबाजारी पर रोक लगाते हुए आंध्र प्रदेश भाजपा इकाई ने राज्य सरकार से किसानों को तत्काल सब्सिडी रेट पर बीज आपूर्ति कराने की मांग की है।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने 20 जून को राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को सब्सिडी रेट पर कपास सहित अन्य बीज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे है। जिस कारण वो आंदोलन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि खुले बाजारों में बेचे जाने वाले बीजों को जब्त कर सरकार को मंडल स्तर पर किसानों को सब्सिडी रेट पर इसे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

भाजपा नेता ने सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए किसानों को हरसंभव मदद पहुंचाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है।

# इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए : भाजपा

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं असम के प्रभारी श्री विजय गोयल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 1 जुलाई से सड़क व नाव मार्ग से असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दो दिवसीय दौरा किया और उसके अगले दिन 2 जुलाई को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी ने भी असम में आई बाढ़ का जायजा लेने के लिए हवाई दौरा किया।

तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में दो सदस्य सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी शामिल थीं।

श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने असम बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए जो 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जो कि पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, सरकार ने उन्हें 10,000 रुपए की राहत देने की घोषणा की है और जिनके घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5000 रूपए। श्री गोयल ने कहा कि इस राहत को भी बढ़ाकर 10,000 से 50,000 एवं 5,000 से 25,000 रुपए किया जाना चाहिए।

श्री गोयल ने कहा कि असम में इससे पहले भी कई बार बाढ़ आती रही है, जिसके कारण जान-माल का काफी नुकसान हुआ है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और इससे निपटने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। बड़े पैमाने पर बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी और जान-माल की हानि को रोकना चाहिए था।

श्री गोयल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर साल असम में आने वाली बाढ़ व उससे पैदा होने वाली तबाही को एक राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखना चाहिए था। 8 साल के केन्द्र और 11 साल के असम राज्य के शासन के बावजूद भी इस संबंध में कुछ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व नियोजित योजना के अभाव में और बाढ़ से निपटने के लिए समय रहते उचित कार्रवाई न किए जाने से हर साल असम में हजारों करोड़ रूपया बाढ़ में डूब जाता है। श्री गोयल ने कहा कि असम में बाढ़ से फसलें खराब हो गई है और कृषि भूमि बालू से भर गई है, जिसके कारण वहां पर खेती नहीं हो सकती। जानवर मर गए हैं, सीवर व्यवस्था एकदम खराब हो गई है, दवाइयों का अभाव

है। श्री गोयल ने कहा कि भाजपा ने असम की बाढ़ के मुद्दे को गंभीरता से उठाया है एवं एक स्थायी समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता असम राज्य के महासचिव श्री प्रद्युत बोरा करेंगे। ■

## ऐतिहासिक चित्र

*भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को पुष्पमाला से अभिनंदन करते लाला हंसराज गुप्ता। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी भी उपस्थित थे।*

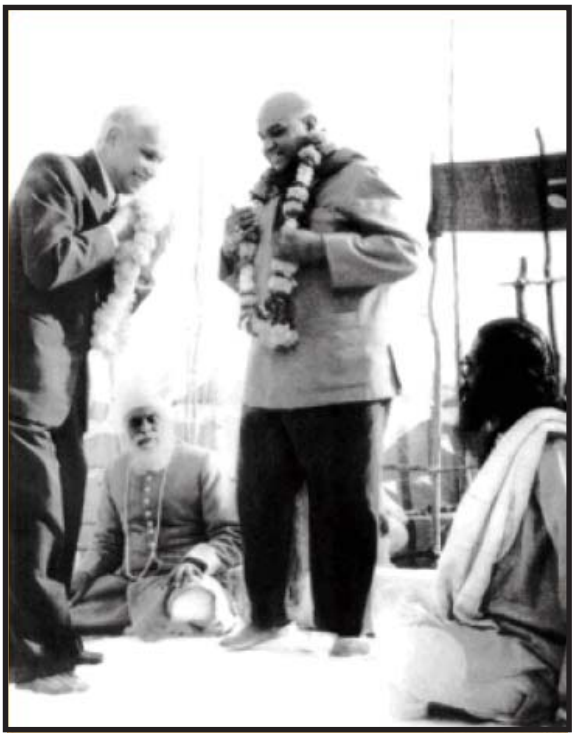

# नक्सल पीड़ित जिलों के बच्चों ने रचा इतिहास

## ए.आई.ई.ई.ई. में 'प्रयास' विद्यालय के 222 में से 149 को मिली कामयाबी

छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित जिलों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए राज्य शासन द्वारा दो वर्ष पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के उत्साहजनक नतीजे अब मिलने लगे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश की राजधानी रायपुर के गुढियारी में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय 'प्रयास' का संचालन किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित गांवों के किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए भी अब इंजीनियर बनने का सपना पूरा होने लगा है।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने लगभग दो वर्ष पहले 26 जुलाई 2010 को इस संस्था का शुभारंभ करते हुए इसके लिए करीब साढ़े चार करोड़ रूपए की लागत से निर्मित विशाल भवन का लोकार्पण किया था। संस्था में मिली गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और स्वयं की मेहनत से 'प्रयास' विद्यालय के दो बच्चों ने जहां इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की कठिन प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की है, वहीं आज घोषित अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) में संस्था के 222 बच्चों में से एक साथ 149 बच्चों ने शानदार कामयाबी हासिल कर एक नया कीर्तिमान बनाया है। किसी एक संस्था से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में कामयाब होना निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण घटना है। इस कठिन चुनौतीपूर्ण प्रवेश परीक्षा में बस्तर और सरगुजा जिले के तीस-तीस, उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले के 21, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले के 14,नारायणपुर जिले के सात, बीजापुर के पांच, जशपुर जिले के दो, कोरिया जिले के एक और राजनांदगांव जिले के 38 छात्रों ने सफलता पायी है।

प्रयास संस्था के छात्र बस्तर संभाग के माकड़ी विकासखण्ड स्थित टेमगांव निवासी शंकर मरकाम अपनी इस सफलता से बेहद खुश हैं। प्रयास संस्था में चयनित होने के बाद उन्हें इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी का मौका मिला। इस सफलता के बाद अब वे सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। शंकर ने आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरसगांव से 85 प्रतिशत अंकों के साथ 10 वीं की परीक्षा पास की थी। इस परीक्षा में सफल सुकमा जिले के छिंदगड़ विकासखण्ड स्थित पुसपाल गांव के निवासी छात्र प्रकाश कुमार बघेल बताते हैं कि पहले उन्होंने पीई.टी. परीक्षा के बारे में भी नहीं सुना था, आई.आई.टी. और ए.आई.ई.ई.ई. तो दूर की बात है। शंकर मरकाम के पिता किसान हैं। प्रकाश कुमार बघेल के पिता भी किसानी थे, जिनका निधन हो चुका है। इन दोनों छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार की इस योजना के जरिए उन्हें पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा मिली। यहां आकर उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले के गौरगांव निवासी अरूण तारम भी अब मेकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। बलरामपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सनवल से 78 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण महेन्द्र कुमार को भी राजधानी रायपुर की प्रयास संस्था में पढ़ने का मौका मिला है। इनके पिता मजदूरी करते हैं। ए.आई.ई.ई.ई. में चयन होने के बाद अब महेन्द्र सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं। इसी संस्था के राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखंड के मिचगांव निवासी कुलदीप ठाकुर ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वे मेकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं। राजनांदगांव जिले के राजाभानपुरी निवासी विनोद कुमार बंधे के पिता किसान है। इस परीक्षा में सफलता के बाद विनोद भी मेकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। ■

**गर्व का क्षण : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे 'प्रयास' विद्यालय के छात्रों ने अपने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के साथ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की।**

# भ्रष्टाचार के आरोपों पर वीरभद्र का इस्तीफा
# कांग्रेस के लिए भारी झटका

– अ. च. वशिष्ठ

आखिरकार, हिमाचल प्रदेश में पांच बार रहे मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह को 25 जून के हिमाचल न्यायालय के निर्णय के बाद त्यागपत्र देना ही पड़ा, जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7, 11, 12 (1) (डी) के अन्तर्गत सीडी मामले में घूस और अपराधिक कदाचरण के लिए स्वयं वीरभद्र सिंह तथा उनकी पूर्व सांसद पत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले का सम्बन्ध उस सीडी से है जिसमें श्री सिंह तथा उनकी पत्नी की आवाज़ें उद्योगपतियों से मौद्रिक लेनदेन के सम्बन्ध में बताई गई हैं।

***विवादित सीडी को पूर्व कांग्रेसी मन्त्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जारी किया था, जो कभी श्री वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। 2007 में श्री सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्हें अपने विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए निष्पक्ष जांच करा के तुरन्त अपने नाम को दाग लगने से बचा लेना चाहिए था। वर्तमान भाजपा सरकार ने वही कुछ किया जो श्री सिंह को करना चाहिए था।***

न्यायालय की आगे की कार्यवाही तभी आगे बढ़ पाएगी जब श्री वीरभद्र सिंह द्वारा दायर याचिका का निर्णय उच्च न्यायालय से आएगा।

अभी दो दिन पहले ही 23 जून को श्री सिंह ने राजनीति में आने के 50 वर्ष पूरे होने तथा अपने 79वीं जन्म दिवस का जश्न मनाया था। उन्होंने शिमला में एक रैली को सम्बोधित करते हुए मांग की थी कि कांग्रेस को चुनाव अभियान शुरू करने से पूर्व मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। स्पष्ट है कि वे स्वयं अपने नाम की घोषणा की वकालत कर रहे थे।

हालांकि पिछले पन्द्रह दिनों में उन्होंने दो बार बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से घोषणा की थी कि यदि न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने का फैसला दे दिया तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, फिर भी वे न्यायालय के निर्णय आने के बाद भी आना-कानी करते रहे। जब न्यायालय का निर्णय आया और मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वह त्यागपत्र दे देंगे तो उन्होंने कहा था कि ''मुझे अपने पद की जरा भी परवाह नहीं हैं। मैं अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं। जैसे और जब भी ऐसा अवसर आएगा तो वह निश्चित ही समुचित कार्रवाई करेंगे।

श्री सिंह शाम को सोनिया गांधी से मिले जिसमें समझा जाता है कि उनसे अपना त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। उन्होंने 26 जून के प्रात:काल अपना इस्तीफा दिया और इसे तुरन्त ही स्वीकार कर लिया गया।

न्यायालय का निर्णय और त्यागपत्र दोनों ही कांग्रेस और श्री सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका है। वह पार्टी के अपने नेतृत्व में विजय की दिशा में ले जाने की उम्मीद बनाए बैठे थी, हालांकि पार्टी उनके हाथों में शासन की बागडोर सौंपने के लिए हिचकिचा रही थी। अभी तक, श्री सिंह की 'स्वच्छ' छवि बनी हुई थी और यह निर्णय उनकी इस बढ़ती उम्र और उनके राजनैतिक जीवन के अंत में उनके लिए बहुत बड़ा दाग बन गया है।

संयोग की बात है कि सीडी की बात 2007 में सामने आई जब राज्य विधान सभा के चुनाव छह महीने में होने वाले थे। इस बार भी न्यायालय का आदेश ऐसे समय में आया है जब नई विधानसभा की चुनावी प्रक्रिया इतने ही समय में पूरी होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुखराम और पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और संयोगत: ये दोनों ही उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडी से जुड़े हैं। इससे राज्य का भी नाम बदनाम हुआ है।

यह राजनेताओं के लिए आम बात है कि जब कभी भी कोई आपराधिक मामले उभर कर आते हैं तो वे अपने राजनैतिक विरोधियों को दोष देते हैं और अपने आरोपों को यह कह कर खारिज करते हैं कि यह सब ''राजनीति से प्रेरित, निराधार और मनगढ़ंत एवं चरित्र-हनन के उद्देश्य से' लगाये गये हैं।

विवादित सीडी को पूर्व कांग्रेसी मन्त्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जारी किया था, जो कभी श्री वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। 2007 में श्री सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्हें अपने विपक्षियों का मुंह बंद करने के लिए निष्पक्ष जांच करा के तुरन्त अपने नाम को दाग लगने से बचा लेना चाहिए था। वर्तमान भाजपा सरकार ने वही कुछ किया जो श्री सिंह को करना चाहिए था। मुख्यमंत्री के रूप में श्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि ''यह न्यायालय का निर्णय है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ■

# 'संगठन की दृष्टि' सांगठनिक दृष्टिकोण एवं विचारधारा का दर्शन

कमल संदेश ब्यूरो

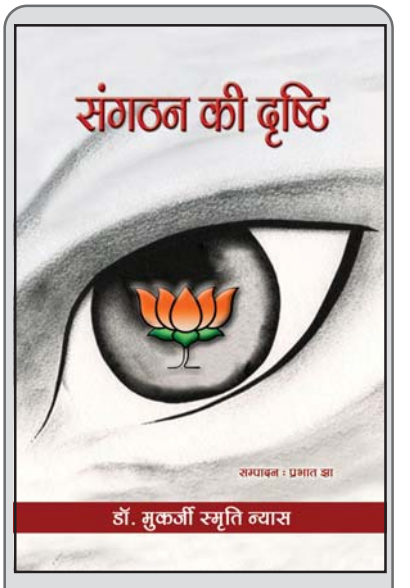


सम्पादक : **प्रभात झा**
प्रकाशक : **डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास**
मूल्य : **250 रुपए**
पृष्ठ : **229**

किसी भी राष्ट्र सामूहिक प्रयास से ही मजबूत होता है और यह प्रयास संगठन की संकल्पना के आधार से प्रवाहित होता है। कोई भी संगठन कुछेक सिद्धांतों, लक्ष्यों और विजन के आधार पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनैतिक संगठन है और उसकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं एवं वह उच्चतम सिद्धांतों और लक्ष्यों को अपना कर चलती है। भाजपा का संगठनात्मक दृष्टि का चित्रांकन समय-समय पर उसके मार्गदर्शकों, चिंतकों और नेताओं ने किया है। संगठन की दृष्टि पुस्तक में जनसंघ-भाजपा अध्यक्षों के चुनिंदा भाषणों का संकलन है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में प्रस्तुत किया था। इन भाषणों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न मुद्दों पर भाजपा की वैचारिक स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए पार्टी की संगठनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की गई है।

पुस्तक का प्रारम्भ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरूजी के मार्गदर्शन से हुआ है। 'अनुशासन: संगठन का मूलमंत्र' में संगठन के अनुशासन की महत्ता को दर्शाया गया है और इसमें विश्व कल्याण के वृहत्तर हितों में प्रभावशाली कामकाज के सिद्धांतों को बताया गया है। ''मार्गदर्शन'' में अनुशासन का महत्त्व सामने रखा गया है क्योंकि इसी से हर प्रकार के प्रलोभनों को दूर करने में मदद मिलती और हम जीवन के बड़े लक्ष्यों की तरफ अपने मन और शारीरिक चैतन्य बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। अनुशासन पर चले बिना किसी भी संगठन के लिए 'मानव कल्याण' के कार्य करना और लक्ष्य प्राप्त करना दुष्कर हो जाता है।

कुछ अन्य चयनित भाषणों में, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी का अध्यक्षीय भाषण विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि यह भाषण 29 दिसम्बर 1952 को कानपुर में आयोजित जनसंघ के प्रथम सम्मेलन के अवसर पर दिया गया था। इस भाषण में विस्तार से उस समय के मुद्दे तथा विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए जनसंघ के गठन की आवश्यकता को दर्शाया गया है। दिसम्बर 1967 में कालीकट अधिवेशन के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अध्यक्षीय भाषण में उस समय के मुद्दों को समाझाया गया है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। 28-30 दिसम्बर 1980 को मुम्बई अधिवेशन हुआ, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ''अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा'' के उद्घोष के पूर्व भाषण देते हुए पाठकों को उस समय की घटनाओं और जनसंघ को भाजपा में अवतरित किए जाने की आवश्यकता से परिचित कराया था और कार्यकर्ताओं को बताया था कि वे चुनौतियों को अवसर में बदल डालें। 9 मई 1986 को दिल्ली सम्मेलन में दिए गए श्री लालकृष्ण आडवाणी के अध्यक्षीय भाषण में छद्म-पंथवाद, आतंकवाद और राष्ट्रीय विचारधारा के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता जैसे मुद्दों पर भाजपा के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। 1-3 फरवरी 1991 के जयपुर अधिवेशन में डॉ. मुरलीमनोहर जोशी के अध्यक्षीय भाषण में पार्टी के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर बल दिया गया है और राष्ट्र को गौरव और महानता प्रदान करने की दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता जताई गई है। श्री कुशाभाऊ ठाकरे, श्री बंगारू लक्ष्मण, श्री के. जना कृष्णमूर्ति, श्री एम. वेंकैया नायडू, श्री राजनाथ सिंह और श्री नितिन गडकरी के अध्यक्षीय भाषणों में विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा की विचारधारा, संगठन और स्थिति सम्बन्धी विशिष्ट आयामों का दिग्दर्शन किया गया है।

पुस्तक का सम्पादन श्री प्रभात झा ने किया है जिसमें जनसंघ-भाजपा अध्यक्षों के अध्यक्षों के विशिष्ट भाषणों के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर संगठनात्मक, वैचारिक और अन्य दृष्टिकोण के अनेकानेक पहलुओं को जोड़ा गया है, जिन्होंने इतिहास के पृष्ठों पर अमिट छाप छोड़ दी है। कार्यकर्ताओं के लिए यह पुस्तक आने वाले समय में उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए पाथेय का काम करेगी। ■

# यदि मनमोहन पर टाइम पत्रिका गलत तो सोनिया मामले में ठीक कैसे?

जब-जब टाइम व फोर्ब्स सरीखी कोई विदेशी पत्रिका कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को विश्व की सशक्तम महिलाओं या प्रभावशाली व्यक्तियों की श्रेणी में खड़ा कर देती हैं तब-तब तो कांग्रेस गद-गद हो जाती है और फूली नहीं समाती। पर अब उसी प्रतिष्ठित साप्ताहिक पत्रिका टाइम ने प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह को एक नाकाम नेता की संज्ञा दी है जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसने उन्हें 'अंडरअचीवर' बताया है। इस पर कांग्रेस तिलमिला उठी है और इस आंकलन को गलत बता रही है।

वाह री कांग्रेस। यदि कोई उसकी तारीफ़ करे तो वह समझदार और अगर बुराई करे तो वह ही बुरा और मूर्ख। पर इससे तो यह भी प्रश्न उठता है कि जिस तर्क व आधार पर डा. मनमोहन सिंह के बारे टाइम पत्रिका का यह आंकलन गलत और झूठा बताया जा रहा है तो उसी तर्क के आधार पर टाइम व फोर्ब्स का श्रीमती गांधी की प्रशंसा में लिखा कैसे सत्य व प्रमाणिक हो सकता है?

## यूपी में भाजपा की शानदार जीत कांग्रेस का सफाया

संप्रग और सपा आपस में मित्र हैं या शत्रु, यह ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर देना बड़े-बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों के लिये भी एक पहेली जैसा है। यह तो निर्भर करता है कि किस समय किस बात पर किस को क्या फायदा होता है। वे किसी बात पर इकट्ठे हैं तो किसी पर घोर विरोधी। इसी विरोधाभास का तब भाण्डा फूट गया जब कांग्रेस के महासचिव रशीद अल्वी ने मुलायम सिंह यादव को भाजपा का एजैण्ट बता कर सब को शशोपंज में डाल दिया। यह बात जनता की भी समझ से बाहर हो गई। अन्त में जनता को बस यही समझ आया कि कांग्रेस व सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो अपने स्वार्थ के लिये समय-समय पर जनता को उल्लू बनाते फिरते हैं।

इस दो-मुंही चाल का जनता ने कांग्रेस व सपा को करारा जवाब दे दिया। अभी हाल ही में हुये स्थानीय निकाय के चुनावों में जनता ने कांग्रेस, बसपा व सपा का सफाया कर दिया। मेयर की 12 में से 10 सीटें जनता ने भाजपा की झोली में डाल कर दोनों ही दलों को स्पष्ट संकेत दे दिया कि ये दोनों ही दल जनता को मूर्ख समझने की गलती न करें। कांग्रेस की सर्वेसर्वा व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व युवाराज राहुल गांधी दोनों के लोक सभा क्षेत्रों में इन स्थानीय चुनावों कांग्रेस का कोई नामलेवा भी न रहा। इस धूलचाटती हार के लिये कौन जिम्मेवार है इस पर अभी दोनों ही महानुभावों ने अपनी जुबान नहीं खोली है।

अपनी झेंप छुपाने के लिये सपा व बसपा दावा कर रही हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी चुनाव निशान पर कोई अधिकृत प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। पर सच्चाई यह है जनता को सब मालूम था कि वह किन-किन उम्मीदवारों को निर्दलीय के रूप में अपना समर्थन दे रही थीं।

इन चुनाव परिणामों ने भाजपा कार्यकताओं में नया जोश पैदा कर दिया है और उनके मनोबल में उछाल आ गया है। इस सारे घटनाक्रम को 2014 के लोक सभा चुनाव का पूर्वाभास माना जा रहा है।

## जिस पर उठी उंगली वही जज

कांग्रेस के राज में सब कुछ सम्भव है। जिस गृह मन्त्री पी विदम्बरम पर 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले में संलिप्त होने के आरोप हैं और मामला न्यायालय के विचाराधी भी है उसी श्री चिदम्बरम को संप्रग सरकार ने मन्त्रियों के सशक्त समूह का मुखिया बना कर अपने ही उस दावे की पोल खोल दी है जिसमें प्रधान मन्त्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में प्रमाणिकता व ईमानदारी को सदैव बनाये रखा है। भाजपा महामन्त्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि श्री चिदम्बरम का इस मामले में अपना निजि हित जगजाहिर है और इस लिये इस कार्य में उन्हें निर्णायक भूमिका देना नैतिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। राजनैतिक विश्लेषकों के मतानुसार मनमोहन सरकार का ऐसा करना एक आरोपित व्यक्ति को ही अपने अपराध पर निर्णय सुनाने का अधिकार देने बराबर है।

## अखिलेश की पैंतराबाजी

उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री अखिलेश यादव ड्रामेबाजी में विश्वास रखते लग रहे हैं। पहले जोश में आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि विधायक विकास निधि में से विधायक अपने लिये 20 लाख रूपये तक की कार खरीद सकते हैं। जब इस पर जनता में तीखी प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने इसी अपने निर्णय को तुरन्त वापस ले लिया। कुछ भी हो जनता के पैसे के सदुपयोग में समाजवादी पार्टी कितनी ईमानदार है, इसका तो पता चल ही गया।

**-अम्बा चरण वशिष्ठ**